वर्ष 13 • अंक 12 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शनिवार 29 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 3

लवासा और सहयोगी कंपनियों के लिए फिर लगेगी बोली

तुलसी तांती पृष्ठ 2

सुजलॉन में निवेश की तैयारी

डॉलर रु. 72.20 ▲ 60 पैसे | यूरो रु. 79.50 ▲ 01.20 रुपये | सोना (10ग्राम) रु 42354 ▼ 88 रुपये | सेंसेक्स 38297.30 ▼ 1448.40 | निफ्टी 11201.80 ▼ 431.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 11149.20 ▼ 52.60 | ब्रेंट क्रूड 50.60 डॉलर ▼ 0.30 डॉलर

एक नज़र

आईओसी बीएस-6 ईंधन आपूर्ति के लिए तैयार

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने शुक्रवार को कहा कि वह कम कार्बन उत्सर्जन वाले बीएस-6 मानकों के अनुकूल ईंधन की आपूर्ति 1 अप्रैल से करने को तैयार है। इससे ईंधन के खुदरा दाम में मामूली वृद्धि होगी। आईओसी के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा कि कंपनी ने कम सल्फर वाले डीजल और पेट्रोल के उत्पादन को लेकर अपनी रिफाइनरी की गुणवत्ता विकास पर पर17,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कीमत वृद्धि के बारे में सिंह ने कहा कि ईंधन के खुदरा दाम में 1 अप्रैल से वृद्धि जरूर होगी लेकिन यह मामूली होगी। पृष्ठ 2

डिजिटल संचार आयोग की बैठक रही बेनतीजा

डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) की शुक्रवार को हुई महत्त्वपूर्ण बैठक में संकट से गुजर रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सूत्रों ने कहा कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये को लेकर आंकड़े नए सिरे से मिलाने के लिए अभी और जानकारियों की जरूरत है। आयोग की अगली बैठक जल्दी ही होने का अनुमान है। पृष्ठ 2

फसल बीमा में नहीं बढ़ेगा किसानों का प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों के प्रीमियम में किसानों के हिस्से में सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी। योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बहुत कम प्रीमियम पर व्यापक फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी तथा नकदी फसलों के लिए 5 प्रतिशत की प्रीमियम दर पर बुआई के पहले से लेकर फसल कटाई के बाद तक के लिए फसल बीमा कवच उपलब्ध कराया जाता है।

कोरोनावायरस का कहर तेजी से फैलने से दुनिया में मची खलबली

कोरोना बुखार से बंटाधार

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 28 फरवरी

कोरोनावायरस के वैश्विक प्रसार की आशंका गहराने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में फैले कोहराम के बीच भारतीय शेयर बाजारों में भी शुक्रवार को पिछले पांच वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के डाऊ जोंस सूचकांक में करीब पांच फीसदी की गिरावट ने सेंसेक्स और निफ्टी को भी दिन भर भारी दबाव में रखा।

घरेलू बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस पर 1449 अंकों यानी 3.6 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 38,297 अंक पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स का 14 अक्टूबर 2019 के बाद का न्यूनतम स्तर है। इसी तरह निफ्टी भी 414 अंकों यानी 3.6 फीसदी की तीव्र गिरावट के साथ 11,219 अंक पर बंद हुआ। घरेलू निवेशकों ने लिवाली की मजबूत धारणा दिखाई लेकिन वैश्विक निवेशकों के हाथ खींचने से बाजार को थाम पाना मुश्किल हो गया। इस दौरान रुपया करीब 0.9 फीसदी की गिरावट के साथ 72.17 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर आ गया। पिछले सात महीनों में भारतीय मुद्रा का यह सबसे निचला स्तर है।

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के सभी क्षेत्रवार सूचकांक और सेंसेक्स के अमूमन सारे घटक नुकसान के साथ बंद हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि सेंसेक्स ने कारोबारी सप्ताह का खात्मा पिछले सप्ताह की तुलना में सात फीसदी की बड़ी गिरावट के साथ किया। दिसंबर 2009 के बाद एक सप्ताह में सेंसेक्स में आई यह सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोनावायरस के महामारी के स्तर तक पहुंच जाने की आशंका जता दी है। इसके बाद दुनिया भर में कोरोना के आर्थिक प्रभावों को लेकर गणनाओं का दौर शुरू हो गया है। हालत यह है कि शुक्रवार को दुनिया के 53 देशों में इस घातक वायरस के संक्रमित मामले पाए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में इस वायरस के मुख्य केंद्र चीन के बाहर भी इसका तीव्र प्रसार देखा गया है।

इसके वैश्विक प्रभाव को देखते हुए ब्रेंट कच्चे तेल के भाव इस हफ्ते 12 फीसदी तक लुढ़क चुके हैं। कारोबारी सप्ताह का समापन इसने 50.8 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर किया। फर्स्ट ग्लोबल के संस्थापक एवं वाइस चेयरमैन शंकर शर्मा कहते हैं, 'इसके पहले हमें घातक वायरस के प्रसार की स्थिति 2003 में सार्स संकट के समय देखने को मिली थी। लेकिन उस समय चीन की अर्थव्यवस्था के इतनी बड़ी नहीं होने से वैश्विक व्यापार पर उसका असर कम रहा था। कोरोना के मामले में अगर हम इसका फैलाव रोक देते हैं तो भी सामान्य स्थिति बहाल करने में कई महीने लग जाएंगे।'

ऐसी स्थिति में कई ब्रोकरेज फर्मों ने आने वाली तिमाहियों में वैश्विक वृद्धि सुस्त रहने के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। यूबीएस में भारतीय शोध के प्रमुख गौतम छाओछाड़िया ने कहा, 'कोरोनावायरस के प्रसार में बाजारों को और नीचे लाने की क्षमता है। अगर इसका प्रसार लंबा रहता है तो इसका वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर बहुत बड़ा असर होगा। हालांकि जल्द ही काबू में आ जाने पर इससे जुड़े जोखिम का प्रतिफल भी काफी आकर्षक होगा।'

बीएसई क्षेत्रवार सूचकांक

सूचकांक	28 फरवरी, 2020	गिरावट प्रतिशत में
धातु	8,240.7	7.0
आईटी	14,987.2	5.6
इन्फ्रा	153.3	4.6
ऑटो	15,568.5	3.8
बैंकेक्स	33,416.2	3.6
रियल्टी	2,123.9	3.4
हेल्थकेयर	13,480.1	3.3
पावर	1,716.8	3.0
ऑयल ऐंड गैस	12,620.0	3.0
कैप गुड्स	15,397.6	3.0

सेंसेक्स, निफ्टी की चाल

तिथि	सेंसेक्स	निफ्टी 50
27/2/2020	39746	11633
28/2/2020	38297	11202
गिरावट प्रतिशत में	3.6	3.7
गिरावट	1448	432

सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले शेयर

शेयर	28 फरवरी	गिरावट
टेक महिंद्रा	743.9	8.1
टाटा स्टील	381.6	7.6
महिंद्रा ऐंड महिंद्रा	456.4	7.5
एचसीएल टेक्नोलॉजीज	534.1	7.0
बजाज फाइनैंस	4,463.1	6.2
इन्फोसिस	731.4	5.9
एसबीआई	302.9	5.9
ऐक्सिस बैंक	696.8	5.3

संकलनः बीएस रिसर्च

ग्राफिक्स:दीपक शर्मा

दुनिया में घमासान के मद्देनजर आर्थिक प्रोत्साहन से पहले सभी देशों को कोरोना वायरस से निपटने पर ध्यान देना चाहिए

रघुराम राजन
आरबीआई के पूर्व गवर्नर

वायरस के डर से जिंस बाजार में भी मची अफरा-तफरी

कोरोनावायरस के असर से जिंस बाजारों में भी खलबली दर्ज की गई। प्रमुख वैश्विक जिंसों की कीमतें शुक्रवार को 1 से 1.32 प्रतिशत तक लुढ़क गईं। भारत में यह गिरावट लगभग 1 प्रतिशत रही। लंदन मेटल एक्सचेंज पर सभी प्रमुख धातुओं में 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पृष्ठ 6

बाजार में गिरावट से प्रवर्तकों को लगी मोटी चपत

बाजार में जबरदस्त बिकवाली से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी की हिस्सेदारी का मूल्य 4.1 प्रतिशत तक कम हो गया। इसी तरह, अदाणी, शिव नाडर और विप्रो के प्रवर्तक अजीम प्रेमजी की हिस्सेदारी को भी तगड़ा झटका लगा। पृष्ठ 3

जीडीपी ने नहीं दी कोई राहत

विनिर्माण एवं निर्माण ने बिगाड़ी चाल

वर्ष	2019-20		
तिमाही	पहली	दूसरी	तीसरी
कृषि	2.8	3.1	3.5
विनिर्माण	2.2	-0.4	-0.2
सेवाएं	6.5	6.4	6.2
निर्माण	5.5	2.9	0.3
सरकारी व्यय	8.7	10.1	9.7

संकलन बीएस रिसर्च

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 28 फरवरी

पिछली दो लगातार तिमाहियों से निवेश एवं विनिर्माण की रफ्तार सुस्त होने से भारत की आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) को तगड़ा झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम होकर महज 4.7 प्रतिशत रह गई। यह पिछली 27 तिमाहयों का सबसे निचला स्तर है। आगे चलकर मार्च तिमाही में भी जीडीपी 4.7 प्रतिशत के स्तर पर रहना लगभग तय हो गया है।

हालांकि दो बातों से थोड़ी राहत जरूर महसूस की जा सकती है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6 प्रतिशत से ऊपर बरकरार है, जिससे अर्थव्यवस्था में जान बरकरार है। देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की आधी से अधिक हिस्सेदारी है। दूसरी अहम बात यह है कि रबी सत्र में उत्पादन बेहतर रहने के संकतों से कृषि क्षेत्र क्षेत्र की वृद्धि दर 3 प्रतिशत से अधिक रही है। दूसरी तरफ उपभोक्ता व्यय लगातार पिछली कई तिमाहियों से 6 प्रतिशत से नीचे रहा है। सरकारी व्यय दूसरी एवं तीसरी तिमाही में क्रमशः 13.2 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत दर से बढ़ा है, जिससे उपभोक्ता व्यय में आई कमी की भरपाई करने में जरूर मदद मिली है।

प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर जनवरी में 2.2 प्रतिशत

आठ प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर जनवरी में 2.2 प्रतिशत दर्ज की गई। यह लगातार दूसरा महीना रहा जब इन क्षेत्रों में मजबूती दर्ज की गई, लेकिन रिफाइनरी उत्पादों एवं बिजली क्षेत्रों का प्रदर्शन कमजोर रहा। पृष्ठ 4

राजकोषीय घाटा पहुंचा 128.5 प्रतिशत पर

राजकोषीय घाटा जनवरी अंत में पूरे वित्त वर्ष के अनुमान के मुकाबले 128.5 प्रतिशत बढ़कर 9.85 लाख करोड़ रुपये हो गया। संशोधित अनुमान में घाटा 7.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था। पृष्ठ 4

दिल्ली हिंसा से ट्रांसपोर्टरों का धंधा पड़ा मंदा

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 28 फरवरी

- हिंसा के कारण ट्रांसपोर्टरों की बुकिंग में 40 प्रतिशत तक कमी
- दिल्ली में बाहरी राज्यों से खरीदार घटने के कारण कारोबार सुस्त
- हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में माल की आवाजाही ठप

दिल्ली में हिंसा की आंच ट्रांसपोर्टरों के कारोबार पर भी आ चुकी है। हिंसा की वजह से ट्रांसपोर्टरों की बुकिंग में कमी देखी जा रही है। बाहरी राज्यों से भी खरीदार कम आ रहे हैं। दूसरी तरफ दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कारखानों और दुकानों में माल की आवाजाही ठप है। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों के धंधे पर चोट पड़ी है।

दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने बताया कि सामान्य दिनों में दिल्ली में रोजाना 40 हजार ट्रक माल आता और जाता है, लेकिन हिंसा के बाद इसमें भारी कमी आई है। इसी तरह, दिल्ली के ट्रांसपोर्टर देविंदर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हिंसा के कारण ट्रांसपोर्टरों की बुकिंग में 30 से 40 प्रतिशत कमी आई है।

उन्होंने कहा, 'इसकी दो अहम वजह है। पहली बात तो यह कि दंगों के कारण बाहरी राज्यों के कारोबारी दिल्ली खरीदारी करने कम आ रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हिंसा प्रभावित सीलमपुर, जाफराबाद, भजनपुरा, चांदबाग, करावल नगर, मौजपुर, शाहदरा आदि इलाकों में कारखाने और दुकानों में कारोबार ठप है। ऐसे में इन इलाकों में माल लाने और यहां से बाहर भेजने के लिए बुकिंग में थम गई है।' ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कारोबार सामान्य होने में समय लगेगा। चांदनी चौक सर्वव्यापार मंडल के महासचिव संजय भार्गव ने कहा कि हिंसा के कारण चांदनी चौक समेत पुरानी दिल्ली के अन्य बाजारों में ग्राहकों की संख्या 30 प्रतिशत से ज्यादा घटी है। इसका असर ट्रांसपोर्टरों की बुकिंग पर पड़ना लाजिमी है।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा भी मानते हैं कि हिंसा के कारण, खासकर, बाहरी राज्यों से कारोबारी कम आने से कारोबार मंदा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को दिल्ली से बाहर माल भेजने के लिए बुकिंग कम मिल रही है।

विमानन कंपनियों पर कोरोनावायरस की मार

अरिंदम मजूमदार और अनीश फडणीस
नई दिल्ली/मुंबई, 28 फरवरी

टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के संयुक्त उपक्रम विस्तारा के लिए पहले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को अपने बेड़े में शामिल करना मील का पत्थर है। कंपनी को घरेलू बाजार में सस्ती सेवा देने वाली कंपनियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और मध्यम तथा लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से उसकी विकास यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। लेकिन विस्तारा के लिए एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। कंपनी ने ड्रीमलाइनर से अपनी पहली उड़ान जापान के लिए संचालित करने की योजना बनाई है लेकिन दुनिया के कई देशों में कोरोनावायरस के प्रकोप से उसकी योजना प्रभावित हो सकती है। विमानन उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि जापान ने देश में स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की है। इससे लोग वहां जाने से परहेज कर सकते हैं और इससे बुकिंग पर असर पड़ सकता है। हालांकि जापान के लिए विस्तारा की पहली उड़ान में अभी एक महीने से अधिक समय है।

एक कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'स्थिति थोड़ा चिंताजनक है लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल या मई तक गर्मी बढ़ने से स्थिति में सुधार आएगा।' विस्तारा पहले ही मार्च में दिल्ली से बैंकॉक के बीच 20 और दिल्ली से सिंगापुर के बीच 8 उड़ानें रद्द कर चुकी है। साथ ही कंपनी मुंबई और सिंगापुर के बीच 26 उड़ानों को भी रद्द करेगी।

माना जा रहा था कि ईंधनों की कीमत में कमी से भारतीय विमानन कंपनियों की स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन दुनियाभर में कोरोनावायरस के प्रकोप से उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है। खासकर ऐसे देश भी इसकी चपेट में आ गए हैं जहां के लिए भारतीय विमानन कंपनियां ज्यादा उड़ानें संचालित करती हैं। इससे इन कंपनियों को अपने नेटवर्क में बदलाव करना पड़ रहा है, उड़ानों में कटौती की जा रही है और नए मार्गों पर प्रस्तावित उड़ानों को टाला जा रहा है।

भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों के बाद कई देश अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी कर रहे हैं।

रेटिंग एजेंसी इक्रा के वाइस प्रेजिडेंट किंजल शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में 19.5 से 23.8 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा, 'यह भारतीय विमानन उद्योग के लिए अच्छी खबर नहीं है जो पहले से यात्रियों की संख्या में भारी कमी से जूझ रहा है। वित्त वर्ष 2020 के पहले नौ महीनों में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में 8.4 फीसदी की कमी आई।'

- सऊदी, दम्माम के लिए उड़ानों की संख्या कम कर सकती हैं इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस
- विस्तारा की जापान के लिए उड़ान शुरू करने की योजना हो सकती है प्रभावित
- टल सकती हैं दम्माम और रास अल खैमा के लिए उड़ान शुरू करने की योजना
- इंडिगो और स्पाइसजेट के शेयर 10 फीसदी लुढ़के

इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस सऊदी अरब और दम्माम के लिए उड़ानों की संख्या में कटौती की योजना बन रही हैं क्योंकि पश्चिम एशिया भी अब कोरोनावायरस की चपेट में आ चुका है।

सऊदी अरब के हज पर प्रतिबंध लगाने के बाद इंडिगो और स्पाइसजेट के अधिकारियों का कहना है कि वे इस क्षमता के अन्यत्र इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब भारतीयों के लिए दूसरा सबसे बड़ा एयर ट्रैवल बाजार है। पिछले साल करीब 59 लाख यात्रियों ने भारत और सऊदी अरब के बीच उड़ान भरी थी।

स्पाइसजेट के एक अधिकारी ने कहा, 'हम उड़ानों की संख्या कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह उस बाजार से नहीं निकल सकते हैं।' कंपनी ने दिल्ली से रास अल खैमा के बीच पहली उड़ान मार्च के पहले सप्ताह में शुरू करने की योजना बनाई थी लेकिन अब इसे टाला जा सकता है।

इंडिगो के एक अधिकारी ने कहा कि क्षमता को व्यावहारिक बनाने के लिए कंपनी रोज एक उड़ान में कटौती कर सकती है। उन्होंने कहा, देश में कई ऐसे गंतव्य हैं जहां इस क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दम्माम के नए लेबर वीजा बनाने पर पाबंदी से कंपनी प्रबंधन चिंतित है। इंडिगो ने 10 मार्च से दम्माम के लिए उड़ान शुरू करने की योजना बनाई थी और अब इस पर अंतिम फैसला वीजा प्रतिबंध की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा।

एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि मार्च में स्कूल दो हफ्ते के लिए बंद हैं और इस दौरान सऊदी अरब की उड़ानों में सीटें भरे रहने की उम्मीद है। हम सऊदी सरकार ये यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि किन लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी और किनको नहीं।

संक्षेप में

केआईओसीएल को कोक ओवन लगाने की मंजूरी

सार्वजनिक क्षेत्र की केआईओसीएल लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि उसे मंगलूरु में कोक ओवन संयंत्र लगाने को हरित मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि यह मंजूरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार कुछ शर्तों पर निर्भर है। मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनी 1.8 लाख टन सालाना क्षमता का कोक ओवन संयंत्र तथा 2 लाख टन सालाना क्षमता के डक्टाइल आयरन स्पन प्राइप (डीआईएसपी) स्थापित करने के लिए है। *भाषा*

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस की पूंजी जुटाने की योजना

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वह ऋण प्रतिभूतियां जारी कर पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने बीएसई से कहा कि वह घरेलू तथा विदेशी बाजारों में सार्वजनिक इश्यू अथवा निजी आधार पर आवंटन के जरिये ऋण प्रतिभूतियां जारी करने समेत कर्ज के विभिन्न विकल्पों से पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि वह कितनी पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। *भाषा*

सुजलॉन में निवेश की तैयारी

सुजलॉन एनर्जी में तांती, सन फार्मा के प्रवर्तक करेंगे 400 करोड़ रुपये तक निवेश

अभिजित लेले
मुंबई, 28 फरवरी

सुजलॉन एनर्जी के प्रवर्तक और सहयोगी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की इस संकटग्रस्त कंपनी में विभिन्न प्रतिभूतियों के जरिये 400 करोड़ रुपये तक का इक्विटी करेंगे। यह निवेश प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के तहत किया जाएगा। कंपनी में तांती होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रवर्तक), सांघवी फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य सहयोगी पूंजी निवेश करेंगे।

कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को दी जानकारी में कहा है कि गुरुवार को देर रात हुई निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी और कुछ सहायक इकाइयों के लिए ऋण पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बीएसई पर कंपनी का शेयर आज 5.9 फीसदी की गिरावट के साथ 2.69 रुपये पर बंद हुआ

ऋण पुनर्गठन योजना के तहत तुलसी तांती के नियंत्रण वाली कंपनी ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए लेनदारों को प्रतिभूतियां- शेयर, परिवर्तनीय बॉन्ड और वारंट- जारी करेगी। उसके लेनदारों में भारतीय स्टेट बैंक, ऐक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और येस बैंक शामिल हैं। पुणे की यह कंपनी अपने कुछ निवेश और परिसंपत्तियों के भी भुनाएगी और इस योजना के मुताबिक कुछ इकाइयों में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि किन परिसंपत्तियों की बिक्री की जाएगी और किन परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी घटाई जाएगी।

बोर्ड ने चार्टर्ड अकाउंटेंट समीर शाह को 27 फरवरी 2020 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उनकी नियुक्ति अगली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

लेनदारों को प्रतिभूतियां जारी करने के मुद्दे पर कंपनी ने कहा कि वह 2 रुपये अंकित मूल्य के 100 करोड़ शेयर जारी करेगी। साथ ही 4.1 लाख सुरक्षित विकल्प वाले परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाएंगे जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1 लाख रुपये होगा। इसके अलावा 1 रुपये मूल्य के 50 करोड़ वारंट जारी किए जाएंगे। कंपनी और लेनदारों ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत पुनर्गठन योजना तैयार की है। उन्होंने 1 जुलाई 2019 को इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (आईसीए) पर हस्ताक्षर किए थे और उसकी अवधि 7 जनवरी 2020 को खत्म हो गई थी। आईसीए के तहत लेनदारों ने संशोधित समझौते को लागू करने की अवधि को 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। अंकेक्षकों ने दिसंबर 2019 तिमाही की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कंपनी गंभीर नकदी किल्लत से जूझ रही है। नकदी किल्लत की चिंता बरकरार रहने के कारण कंपनी के परिचालन जारी रखने की क्षमता पर भी सवाल उठने लगे थे।

सुजलॉन की योजना

- प्रवर्तक करेंगे 400 करोड़ रुपये तक का इक्विटी निवेश
- लेनदार अपने ऋण के कुछ हिस्से को इक्विटी में बदलेंगे
- कुछ परिसंपत्तियों को बेचने और भुनाने की योजना
- 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी जारी करने के लिए प्रस्ताव
- क्रिसिल ने औसत जोखिम के साथ योजना को 'आरपी4' रेटिंग दी

बीएस6 से ग्राहकों को नहीं लगेगा झटका

अमृता पिल्लई
मुंबई, 28 फरवरी

सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कंपनी बीएस6 उत्सर्जन मानदंड के अनुरूप ईंधन के लिए निर्धारित अप्रैल की समय-सीमा पर खरी उतरेगी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस स्वच्छ ईंधन के लिए मूल्य वृद्धि का मुद्दा पहले ही सुलझा लिया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल विपणन कंपनियों- इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) ने बीएस6 श्रेणी के ईंधन उत्पादन के लिए रिफाइनरी के उन्नयन पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अकेले इंडियन ऑयल ने अपनी रिफाइनिंग इकाइयों के उन्नयन पर करीब 17,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इंडियन ऑयल के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा, 'यदि उद्योग इसके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहा है तो हमारा मानना है कि इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मूल्य वृद्धि उतनी नहीं होगी जो आपको (खुदरा ग्राहकों को) चुभेगी।' बीएस6 उन्नयन के मद्देनजर बीपीसीएल 70 पैसे से 1.30 रुपये प्रति लीटर मूल्य वृद्धि करना चाहती है जबकि इंडियन ऑयल की नजर 50 पैसे से 1 रुपये प्रति लीटर मूल्य वृद्धि पर है। सिंह ने यह भी कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमत 1 अप्रैल से यूरो6 पर आधारित होगी जो फिलहाल यूरो4 पर आधारित है।

इंडियन ऑयल

- पेट्रोल पंप (किसान सेवा केंद्र आरओ सहित) **27,702**
- टर्मिनल और डिपो की संख्या **125**
- चालू रिफाइनरी की संख्या **9**

स्रोतः कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2019

डीसीसी की बैठक बेनतीजा

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 28 फरवरी

लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपये के लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान के संकट से जूझ रहे दूरसंचार उद्योग के लिए केंद्र सरकार द्वारा राहत पैकेज की राह में अपर्याप्त डेटा बाधक बन रहा है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत उपायों की उम्मीद के साथ शुक्रवार को हुई डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (डीसीसी) की बैठक डेटा मुद्दे पर विफल साबित हुई। माना जा रहा है कि निर्णय लेने वाली उच्च पदस्थ संस्था डीसीसी को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना के लिए डेटा में विसंगति का सामना करना पड़ रहा है।

डीओटी सचिव की अध्यक्षता वाली डीसीसी में वित्त, वाणिज्य और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के सचिवों के अलावा नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी भी शामिल हैं।

डीसीसी के सदस्यों ने दो घंटे चली बैठक के दौरान हुई चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि एजीआर डेटा के मिलान के लिए और ज्यादा विवरण की जरूरत है। डीसीसी द्वारा आने वाले दिनों में फिर से बैठक किए जाने की संभावना है।

मुंबई ब्लॉक से दिसंबर तक उत्पादन शुरू करेगी हिंदुस्तान ऑयल

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 28 फरवरी

चेन्नई की हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी) मुंबई में खोजे गए अपने लघु क्षेत्र (डीएसएफ) से दिसंबर तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी ने इस महीने के आरंभ में इस ब्लॉक के पहले कुएं की खुदाई सफलतापूर्वक की थी। कंपनी डीएसएफ नीलामी दौर के तहत कच्चे तेल का उत्पादन शुरू करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी।

कंपनी के प्रबंध निदेशक पी एलंगो ने कहा, 'हम खोजे गए संसाधनों को भुनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम दिसंबर तक बी-80 (ब्लॉक) में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद करते हैं। खोजे गए क्षेत्रों में उत्पादन शुरू होने पर कुल मिलाकर उत्पादन दोगुना होने का अनुमान है।' दूसरे कुंए की खुदाई अप्रैल तक पूरी होने की उम्मीद है। खोजे गए क्षेत्र से उत्पादन ऐसे समय में शुरू होने जा रहा है जब डीएसएफ के पहले और दूसरे दौर के तहत कई ब्लॉक अटके पड़े है। बी-80 के लिए क्षेत्र विकास योजना में तेल एवं गैस के उत्पादन के लिए दो कुओं की खुदाई शामिल है।

डीएसएफ बोली दौर 2016 के तहत एचओईसी को यह ब्लॉक मिला था और उस दौरान 22 कंपनियों को 31 क्षेत्रों के लिए अनुबंध दिए गए थे। उसी दौरान इस क्षेत्र में 15 नई कंपनियों ने प्रवेश किया था।

इससे पहले चर्चा थी कि एचओईसी इस ब्लॉक से तेल एवं गैस के उत्खनन के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचा क्षेत्र की दिग्गज सरकारी कंपनी ओएनजीसी के साथ बातचीत कर रही थी। इस ब्लॉक से गैस की आपूर्ति ओएनजीसी के हजीरा संयंत्र को और तेल की आपूर्ति उसके उरण संयंत्र को करने की योजना थी।

इस ब्लॉक में अद्भुत एस्टेट्स के साथ एचओईसी की 50 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी ने कथित तौर पर इस ब्लॉक में निवेश के लिए 6 करोड़ डॉलर रखा था। डीएसपी की नीलामी नई उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) को बदलने वाली हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) के तहत हुई थी। डीएसएस के दूसरे दौर में 25 अनुबंध क्षेत्रों का आवंटन हुआ था।

कंपनी की नजर 2020 की पहली छमाही तक अपने शुद्ध उत्पादन को करीब दोगुना बढ़ाकर 5,000 बैलर तेल समतुल्य प्रति दिन (बओईपीडी) करने की है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अंत में कंपनी ने 3,233 बीओईपीडी उत्पादन दर्ज किया था।

पिछले साल असम के डिरोक क्षेत्र से उत्पादन में कटौती की गई थी। यह कटौती मुख्य तौर पर ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन (बीवीएफसीएल) जैसे प्रमुख ग्राहकों के संयंत्रों की आंशिक बंदी और हड़ताल के कारण हुई थी। नामरप में बीवीएफसीएल के अमोनिया-यूरिया संयंत्र में जनवरी में जोरदार धमाका हुआ था। इससे डिरोक से आपूर्ति प्रभावित हुई।

एलंगो ने कहा, 'असम में स्थानीय विरोध-प्रदर्शन के कारण डिरोक में उत्पादन प्रभावित हुआ था।'

भारत में जल्द होगी बेहतर औषधि निगरानी व्यवस्था

सोहिनी दास
मुंबई, 28 फरवरी

भारत दवाओं व मेडिकल उपकरणों के मामले में गुणवत्ता में सुधार व बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठा रहा है।

मानव संसाधन लेने के अलावा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) सुगम पोर्टल विकसित करने में भी निवेश करेगा, जिसमें देश में उपलब्ध सभी दवाओं की सूची होगी और उनके विनिर्माताओं व लाइसेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे भारत में दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला के बारे में जानना सुगम होगा।

भारत के औषधि महानियंत्रक वीजी सोमानी ने कहा कि सरकार ने पहले ही परियोजना के लिए 1,850 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें दवा व मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता व्यवस्था पर नजर रखने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि इस धन का बड़ा हिस्सा सुगम पोर्टल को विकसित करने में लगाया जाएगा, जो सीडीएससीओ का ई-गवर्नेंस सॉल्यूशन है।

लवासा, 49 सहायक फर्मों के लिए फिर लगेगी बोली

देव चटर्जी और रघु मोहन
मुंबई, 28 फरवरी

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से मूल कंपनी व सहायक कंपनियों की समाधान योजना के एकीकरण के फैसले के बाद लवासा कॉरपोरेशन लिमिटेड के लेनदारों ने इस कंपनी और 49 सहायक फर्मों के लिए दोबारा बोली मंगाने का निर्णय लिया है। लवासा पुणे के पास निर्माणाधीन पर्वतीय शहर है।

लवासा और उसकी सहायक फर्मों पर संयुक्त रूप से करीब 7,700 करोड़ रुपये का कर्ज है, ऐसे में बैंकों ने कर्ज समाधान के लिए अगस्त 2018 में कंपनी को एनसीएलटी में घसीट लिया।

एक सूत्र ने कहा, लवासा के पिछले बोलीदाताओं के पास लवासा और उसकी सहायक फर्मों को एक साथ खरीदने की वित्तीय क्षमता शायद नहीं होगी, ऐसे में लेनदारों ने बुनियादी ढांचे के साथ पूरे पर्वतीय शहर में दिलचस्पी रखने वालों से नई बोली मंगाने का फैसला लिया है। कई कंपनियों ने लवासा के लिए एकल इकाई के तौर पर अपनी-अपनी पेशकश जमा कराई है। इनमें दिल्ली की हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के बिल्डर अनिरुद्ध देशपांडे और यूवी ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी (यूवी एआरसी) शामिल है। बाद में ओबेरॉय रियल्टी व अमेरिका की फंड इंटरप्स इंक भी इस दौड़ में शामिल हो गई।

मूल रूप से एचसीसी ने लवासा कॉरपोरेशन की स्थापना पुणे में साल 2000 में की थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से साल 2010 में परियोजना के लिए कार्य आदेश जारी करने पर रोक के बाद उसने बैंक के कर्ज भुगतान में चूक की। तब से यह भुतहा शहर बन गया है और सप्ताहांत में कुछ पर्यटक इस जगह को देखने आते हैं। घर खरीदने वाले कई लोग या तो अपने मकान के पजेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिन्हें पजेशन मिल गया है वे वहां से बाहर निकल गए हैं।

एनसीएलटी में सुनवाई के दौरान लवासा के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने कहा कि कुछ बोलीदाताओं ने लवासा कॉरपोरेशन के 6,200 करोड़ रुपये के एकल कर्ज के समाधान के बजाय लवासा की सभी कंपनियों के कर्ज समाधान का प्रस्ताव रखा था। हालांकि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने अदालत को सूचित किया कि इन शर्तों पर फैसला लेने का अधिकार लवासा के पास नहीं है क्योंकि अलग-अलग बैंकरों के साथ कई अन्य कानूनी इकाइयां हैं।

अदालत को यह भी बताया गया कि मूल कंपनी लवासा के साथ सहजीवी संबंध है, ऐसे में इन सहायक कंपनियों में से कई अपने राजस्व का स्रोत खो देंगे, इसलिए इन सभी के लिए समाधान योजना के एकीकरण का मतलब बनता है।

ये कंपनियां लवासा को कैप्टिव पावर देने के अलावा आधारभूत परिवहन का परिचालन कर रही हैं, कन्वेंशन सेंटर का परिचालन व रखरखाव कर रही हैं और लवासा कॉरपोरेशन की इमारतों के भीतर खुदरा परिचालन भी कर रही हैं। एक अलग कंपनी लक्जरी होटल का परिचालन कर रही है।

ऐसे में अदालत का मानना था कि इन कंपनियों के जुड़ाव को देखते हुए लवासा कॉरपोरेशन को परिचालन में बनाए रखना अहम है ताकि सभी कंपनियों के लिए अधिकतम कीमत हासिल हो सके। ऐसे में सभी बोलीदाताओं के लिए इन कंपनियों के लिए एक पेशकश के जरिए बोली लगाना अहम होगा।

अदालत ने कहा, दिलचस्प रूप से पिछले तीन बोलीदाताओं ने समाधान योजना के पूर्व शर्त के तौर पर एकीकरण की बात कही थी। इसलिए एकल आधार पर इन कं पनियों के लिए समाधान योजना की खोज मुश्किल होगी। हालांकि अगर लवासा कॉरपोरेशन की सभी कंपनियों का समाधान एकीकृत आधार पर किया जाए तो समाधान के जरिए अधिकतम कीमत हासिल की जा सकती है।

समाधान में देर

- **अगस्त 2018 :** लेनदारों ने लवासा को कर्ज समाधान के लिए एनसीएलटी में घसीटा
- **नवंबर 2018 :** लवासा के लिए संभावित बोलीदाताओं से अभिरुचि पत्र आमंत्रित
- **मई 2019 :** लवासा के लिए तीन कंपनियों ने पेशकश जमा कराई, बोलीदाताओं ने सभी कंपनियों के एकीकरण की मांग की
- **जनवरी 2020 :** ओबेरॉय रियल्टी, अमेरिकी फंड इंटरप्स इस दौड़ में शामिल हुई

एक हफ्ते में करीब 3,000 अंक टूटा सेंसेक्स, आगे क्या होगा ?

बिजनेस स्टैंडर्ड ने शेयर बाजार पर कोरोनावायरस के असर का आकलन किया

समी मोडक
मुंबई, 28 फरवरी

कोरोनावायरस के प्रसार के कारण आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए वैश्विक स्तर पर इक्विटी की बिकवाली के बीच भारतीय बाजार शुक्रवार को तीन फीसदी टूट गए। पिछले एक हफ्ते में भारतीय बाजार सात फीसदी टूटा है। कुछ वैश्विक बाजार गिरावट के दौर में चले गए हैं। निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे बाजार और कितना फिसल सकता है। इसका जवाब इस पर निर्भर है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया कितनी सक्षम हो पाती है। मॉर्गन स्टैनली ने तीन परिदृश्य सामने रखा है। इसका कहना है कि कोरोना अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है। हमने इन परिदृश्यों का आकलन किया।

परिदृश्य 1 (मार्च तक वायरस पर लगाम) : वायरस के प्रसार पर मार्च के आखिर तक रोक लग जाएगी और चीन में उत्पादन की गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी और यह 2020 की पहली तिमाही में अवरोध को सीमित कर देगा। पहली तिमाही में वैश्विक बढ़त की रफ्तार घटकर 2.5 फीसदी रह जाएगी, जो 2019 की चौथी तिमाही में 2.9 फीसदी थी। लेकिन दूसरी तिमाही से इसमें ठीक-ठाक सुधार होगा।
बाजार पर असर : हालिया बिकवाली, खरीदारी का अच्छा मौका साबित होगी। दुनिया भर में शेयरों में सुधार हो सकता है।

परिदृश्य 2 - नए इलाकों में इसका प्रसार होगा और अवरोध दूसरी तिमाही में जारी रहेगा (जून तिमाही) : मई के आखिर में सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने से पहले दुनिया के दूसरे इलाकों में नए मामले आते रहेंगे। दूसरी तिमाही में भी अवरोध जारी रहेगा। वैश्विक बढ़त की रफ्तार पहली छमाही में औसतन 2.4 फीसदी रहेगी, लेकिन तीसरी तिमाही से यह जोर पकड़ेगा।

बाजार पर असर : बाजार में सुधार का मामला लंबा खिंचेगा। शेयरों में जल्दी सुधार नहीं होगा।

परिदृश्य 3 - सितंबर तिमाही में इसके बने रहने से मंदी का जोखिम बढ़ेगा : वायरस का प्रसार तीसरी तिमाही में जारी रहेगा और यह सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक होगा। चीन में नए मामले बढ़ते रहेंगे। तीसरी तिमाही में अवरोध बना रहेगा। वैश्विक रफ्तार पहली व तीसरी तिमाही के बीच कमजोर बनी रहेगी॥
बाजार पर असर : यह कंपनियों के लाभ पर चोट पहुंचाने वाला साबित होगा। यह कंपनियों की तरफ से डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ा सकता है। वैश्विक केंद्रीय बैंकों व नीति निर्माताओं को वैश्विक रफ्तार में इजाफे के लिए साल 2008 जैसे कदम उठाने होंगे। शेयर बाजार में गिरावट लंबे समय तक बनी रहेगी।

मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि दूसरे परिदृश्य की संभावना ज्यादा है और कोरोना बीमारी का अर्थव्यवस्था व बाजारों पर अस्थायी असर होगा।

ब्रोकरेज ने शुक्रवार को एक नोट में कहा, वैश्विक व्यापार चक्र के आकलन के नजरिये से हमारा मानना है कि आर्थिक मंदी के मुकाबले कोरोना बीमारी अस्थायी झटका देगी। हमारा अब भी मानना है कि सुधार में भले ही देर है, लेकिन यह पटरी से नहीं उतरा है।

साल 2008 के बाद का सबसे खराब सप्ताह

ज्यादातर वैश्विक बाजारों ने साल 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद सबसे खराब सप्ताह का सामना किया है क्योंकि कोरोनावायरस के प्रसार से निवेशक सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। इक्विटी बाजार में हालांकि गिरावट आई, लेकिन बॉन्ड बाजारों में तेजी दर्ज हुई और अमेरिकी ट्रेजरी पर प्रतिफल घटकर 1.2 फीसदी से नीचे आ गया, जो 2016 के बाद का निचला स्तर है। एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाजारों में शेयरों में गिरावट की रफ्तार काफी तेज रही। यह गिरावट इतनी तेज थी कि एसऐंडपी 500 इंडेक्स ने महज छह कारोबारी सत्र में 10 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज कर गिरावट वाले क्षेत्र में प्रवेश का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय बाजार भी गिरावट वाले क्षेत्र में प्रवेश के करीब है। पिछले दो साल में ऐसे मौकों पर देसी बाजारों में गिरावट के बाद तेज सुधार देखने को मिला है। क्या इस बार भी बाजार फिर से पटरी पर आ जाएगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या कोरोनावायरस को फैलने से रोक लिया गया है।

एक दशक का सबसे बड़ा झटका

ज्यादातर विदेशी बाजारों में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की सबसे गिरावट रही

सूचकांक	देश	बदलाव (फीसदी) एक दिन	एक हफ्ते	इस साल अब तक
डाउ जोन्स	अमेरिका	-4.4	-11.8	-9.7
बोवस्पा	ब्राजील	-2.6	-10.4	-10.9
यूरो स्टॉक्स 50	यूरोजोन	-3.1	-11.9	-10.6
एफटीएसई 100	ब्रिटेन	-3.0	-10.9	-12.6
डैक्स	जर्मनी	-3.5	-12.1	-9.9
निक्केई 225	जापान	-3.7	-10.0	-10.6
कोस्पी	द. कोरिया	-3.3	-8.1	-9.6
शांघाई कम्पोजिट	चीन	-3.7	-5.2	-5.6
निफ्टी 50	भारत	-3.7	-7.3	-7.9
थाइ इंडेक्स	थाइलैंड	-3.9	-10.3	-15.1

स्रोत : ब्लूमबर्ग। संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

पंजाब में हेरिटेज फूड्स के प्लांट का अधिग्रहण करेगी अमूल डेयरी

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 28 फरवरी

गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) की अहम कंपनी अमूल डेयरी 21.20 करोड़ रुपये में हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के डेयरी प्लांट का अधिग्रहण करेगी। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को फतेहगढ़ साहिब जिले के भांबरी गांव में स्थित डेयरी प्लांट की सभी मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री को मंजूरी दे दी। कंपनी ने एक्सचेंजों को भेजी सूचना में ये बातें कही है। यह कदम उत्तर भारत में कारोबार को व्यावहारिक बनाने वाले कदमों का हिस्सा है। निदेशक मंडल ने आणंद की अमूल डेयरी को बिक्री को मंजूरी दे दी।अब जीसीएमएमएफ अधिग्रहण प्रस्ताव का आकलन कर रहा है और निदेशक मंडल इस पर जल्द ही फैसला लेगा क्योंकि वह उत्तर भारत में दूध, दही और छाछ के अलावा अन्य डेयरी उत्पादों की मांग पूरी करने के लिए पंजाब में अपने परिचालन का विस्तार करना चाहता है।

जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक आर एस सोढी ने कहा, हम अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हम उत्तर भारत खास तौर से पंजाब में अपने परिचालन का विस्तार कर रहे हैं और हमें और उत्पादन केंद्र की दरकार है क्योंकि हमारी बिक्री बढ़ रही है।अभी जीसीएमएमएफ के दो छोटे प्लांट पंजाब में हैं, जो दूध, दही और छाछ का उत्पादन करता है।

निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान

शेयर बाजारों में शुक्रवार को आई भारी गिरावट से निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की चपत लगी है। कोरोनावायरस के फैलने और उसके आर्थिक प्रभाव को देखते हुए बिकवाली निकलने से बाजार में गिरावट रही तथा निवेशकों को नुकसान हुआ।

कुल छह कारोबारी सत्रों में बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 11,76,985.88 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण निवेशकों को 5,46,287.76 करोड़ रुपये की चपत लगी। इससे सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 1,46,93,797.43 करोड़ रुपये पर आ गया। गुरुवार को इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,52,40,024.08 करोड़ रुपये था। *भाषा*

बिकवाली से प्रवर्तकों को पड़ी सबसे ज्यादा चोट

प्रवर्तक/परिवार	मूल कंपनी	हिस्सेदारी की मौजूदा कीमत*	हफ्ते में बदलाव वैल्यू (करोड़ रुपये)	फीसदी	28 फरवरी को बदलाव वैल्यू (करोड़ रु.)	फीसदी
मुकेश अंबानी	रिलायंस इंडस्ट्रीज	411614.0	-48591.7	-10.6	-17704.8	-4.1
अदाणी	अदाणी पोर्ट्स एसईजेड	125165.6	-24621.6	-16.4	-6301.7	-4.8
शिव नाडर	एचसीएल टेक	87045.5	-12067.4	-12.2	-6525.7	-7.0
अजीम प्रेमजी	विप्रो	93525.7	-10342.1	-10.0	-4441.3	-4.5
आर डी दमानी	एवेन्यू सुपरमार्ट्स	119368.4	-7776.3	-6.1	-455.4	-0.4
कुमार मंगलम बिड़ला	ग्रासिम इंडस्ट्रीज	49395.4	-7145.0	-12.6	-2436.1	-4.7
अनिल अग्रवाल	वेदांत	23232.4	-5739.5	-19.8	-3237.2	-12.2
आदि गोदरेज	गोदरेज कंज्यूमर	45009.2	-5091.9	-10.2	-2489.4	-5.2
रवि भाटिया, राकेश गंगवाल	इंटरग्लोब एविएशन	37468.1	-4731.0	-11.2	-1890.7	-4.8
दिलीप सांघवी	सन फार्मा	51439.2	-4561.3	-8.1	-2194.1	-4.1
नुकसान उठाने वाले 10 अग्रणी		1043263.4	-130667.9	-11.1	-47676.3	-4.4
सभी प्रवर्तक		3058243.3	-275404.2	-8.3	-119240.6	-3.8

* समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में 28 फरवरी को कारोबार बंद होने के बाद प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की संयुक्त कीमत।
स्रोत : कैपिटालाइन, बीएस का आकलन

ओरिएंटल इंश्योरेंस को 3,000 करोड़ रुपये की जरूरत!

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 28 फरवरी

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा दिग्गज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वित्त वर्ष 2021 में अपनी विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत हो सकती है।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक ए वी गिरिजाकुमार के अनुसार, यह पूंजी विकास योजनाओं के वित्त पोषण और सॉल्वेंसी अनुपात बनाए रखने के लिए जरूरी होगी। हालांकि वास्तविक विकास योजना बीमा कंपनी को सरकार से मिलने वाली पूंजीगत सहायता के आधार पर तैयार की जाएगी। कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 18 मार्च को होगी, जिसमें आगामी वित्त वर्ष में बढ़त के लिए बजट की जांच होगी।

गिरिजाकुमार ने कहा, हमें बढ़त और वित्त वर्ष 2021 में नियामकीय सॉल्वेंसी जरूरतें पूरी करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये की पूंजी की दरकार हो सकती है, हालांकि हमारी कारोबारी योजना हमें मिलने वाली पूंजी के मुताबिक बनेगी। उन्होंने मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बातें कही।

इस साल पेश बजट में तीन बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 6,950 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

बुनियादी उद्योगों में लगातार दूसरे महीने आई मजबूती

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 28 फरवरी

अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों में लगातार दूसरे महीने मजबूती दर्ज की गई और जनवरी में इसमें 2.2 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। इस सुस्त वृद्धि की वजह यह है कि रिफाइनरी उत्पादों और विद्युत जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगातार धीमी रफ्तार की स्थिति बनी हुई है। नवंबर तक प्रमुख क्षेत्र के उत्पादन में लगातार चार महीनों से संकुचन की स्थिति कायम रही थी। इसके नतीजतन चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जनवरी की अवधि में प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन घटकर 0.6 फीसदी रह गई जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि यह 4.4 फीसदी रही थी।

आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में जनवरी में 1.9 फीसदी की वृद्धि हुई जो दिसंबर में नजर आई 3 फीसदी की वृद्धि से कम है। वित्त वर्ष 2020 में जहां यह क्षेत्र उतार चढ़ाव से भरा रहा, वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उत्पादन में एक मजबूत सुधार नजर आने लगी है क्योंकि प्रमुख शोधन इकाइयां जो पहले बंद पड़ी थी अब चालू हो गई हैं।

जनवरी में कोयले के उत्पादन में सर्वाधिक उछाल नजर आई और उस महीने यह 8 फीसदी रही जबकि उससे पिछले महीने यह 6 फीसदी रही थी। इस क्षेत्र में नवंबर तक संकुचन की स्थिति बरकरार रही थी जिसके पहले जुलाई तक लगातार 24 महीने इसमें वृद्धि की स्थिति दर्ज की गई थी। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार नीचे जा रहा है जहां पिछले 16 महीनों से लगातार संकुचन की स्थिति बनी हुई है।

उत्पादन में 5.3 फीसदी की कमी आई जबकि दिसंबर में 7.4 फीसदी की कमी आई थी।

नवंबर 19 में क्षेत्रवार वृद्धि दर

क्षेत्र	सालाना वृद्धि (%)
कोयला	8
कच्चा तेल	-5.3
प्राकृतिक गैस	-9.1
रिफाइनरी उत्पाद	1.9
उर्वरक	-0.1
स्टील	2.2
सीमेंट	5.0
बिजली	2.8
कुल	2.2

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

प्रमुख क्षेत्रों ने लाई सुस्ती

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 28 फरवरी

कोयले के उत्पादन, कच्चे तेल के उत्पादन, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री, हवाईअड्डों पर कार्गो की आवाजाही सहित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रमुख संकेतकों की गणना ने वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिखाई है।

वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री का उदाहरण लें तो यह वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 17.3 प्रतिशत कम हुई है, जबकि वित्त वर्ष 19 की तीसरी तिमाही में इसकी वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी। इसी तरह से कोयले का उत्पादन 4.3 प्रतिशत गिरा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी।

सीमेंट, स्टील, प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन इसकी वृद्धि दर वित्त वर्ष 19 की तीसरी तिमाही की तुलना में बहुत मामूली है। उदाहरण के लिए तीसरी तिमाही में स्टील की खपत महज 0.3 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत थी। इसी तरह से प्रमुख समुद्री बंदरगाहों पर कार्गो से ढुलाई 0.1 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि एक साल पहले 1.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

सिर्फ 2 संकेतकों में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें सकल बैंक जमा और उपभोक्ता मूल्य पर आधारित (सीपीआई) महंगाई दर शामिल है। सकल बैंक जमा में वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही में 9.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इसके पहले के वित्त वर्ष की समान तिमाही में 8.9 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इससे निवेश की संभावना में कमी के संकेत मिलते हैं।

ईवाई में मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा, 'बैंक जमा में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि निवेश का माहौल नहीं बन पाया। इससे निवेश के विभिन्न माध्यमों में अनिश्चितता के संकेत मिलते हैं।'

वहीं दूसरी तरफ सीपीआई महंगाई दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गई है, जो एक साल पहले 2.6 प्रतिशत थी। वहीं थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 1 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 4.5 प्रतिशत बढ़ी थी। जीडीपी के आंकड़ों में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों के ही आंकड़े शामिल किए जाते हैं, जो क्षेत्रों पर निर्भर है।

कीमतों की चाल का शुद्ध असर यह रहा कि जहां मौजूदा भाव पर जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही में 7.7 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 11.4 प्रतिशत थी, वहीं स्थिर मूल्य पर जीडीपी वृद्धि 4.7 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत थी।

चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल बैंक कर्ज में मामूली बढ़ोतरी हुई। तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 13.9 प्रतिशत थी।

जीडीपी की गणना के मुख्य संकेतक

जिंस	2018-19 तीसरी तिमाही	2019-20 तीसरी तिमाही	2018-19 के पहले 9 माह में	2019-20 के पहले 9 माह में
कोयले का उत्पादन	5.1	-4.3	7.9	3.8
कच्चे तेल का उत्पादन	-4.3	-6.2	-3.7	-6
प्राकृतिक गैस का उत्पादन	1.5	-6.6	-0.2	-3.2
सीमेंट का उत्पादन	12.9	0.6	13.9	0.7
स्टील की खपत	8.2	0.3	9.1	3.5
वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	6.7	-17.3	25.9	-21.7
प्रमुख बंदरगाहों पर कॉर्गो	1.4	0.1	3.8	1
हवाईअड्डों पर कार्गो	2.2	-7.2	3.8	-7.5
हवाईअड्डों पर यात्री	10.7	4.6	14.5	1.8
रेलवे शुद्ध टन किमी	5.7	-4.7	6.9	-3.6
रेलवेः यात्री किमी	-2.4	-1	6.9	-3.6
सकल बैंक जमा	8.9	9.7	7.9	9.8
सकल बैंक कर्ज	13.9	7	12.4	9.2
सीपीआई महंगाई दर	2.6	5.8	3.7	4.1
डब्ल्यूपीआई महंगाई दर	4.5	1	4.7	1.5
जीडीपी वृद्धि	5.6	4.7	6.3	5.1

तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5 फीसदी वृद्धि

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 28 फरवरी

वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में देश के कृषि क्षेत्र ने 3.5 फीसदी वृद्धि हासिल की है। इसमें खरीफ सीजन में अच्छे उत्पादन और रबी सीजन में भारी पैदावार की संभावना की अहम भूमिका रही है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलने के आसार हैं क्योंकि इस अवधि में महंगाई 10.2 फीसदी रहने का अनुमान है। महंगाई का यह स्तर कई तिमाहियों में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि महंगाई को कभी-कभी कृषि आय का संकेतक माना जाता है।

तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि बढ़ने से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का अनुमान है कि पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में इस क्षेत्र की वृद्धि स्थिर कीमतों पर 3.7 फीसदी रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2018-19 इस क्षेत्र की वृद्धि 2.4 फीसदी से अधिक होगी।

इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि चालू कीमतों पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि 2019-20 में 11.3 फीसदी अनुमानित है, जो 2018-19 में 4.5 फीसदी से अधिक है। इसमें खाद्य कीमतों की ऊंची कीमतों की अहम भूमिका रही है। इसका मतलब है कि 2019-20 में महंगाई 7.6 फीसदी रहने के आसार हैं।

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'सहायक क्षेत्रों, मुख्य रूप से पशुपालन, मत्स्यपालन और बागवानी से जुड़े किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलने के आसार हैं। इनकी कृषि गतिविधियों में करीब 45 फीसदी हिस्सेदारी है। यही वजह है कि चालू कीमतों पर वृद्धि 11.3 फीसदी अनुमानित है।'

कुछ दिन पहले जारी खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान में गेहूं का उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,062.1 लाख टन रहने की संभावना जताई गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 2019 से शुरू फसल वर्ष 2019-20 में गेहूं का उत्पादन 2018-19 की तुलना में 26.1 लाख टन और इस साल के लक्ष्य से 57.1 लाख टन अधिक रहने का अनुमान है।

- खरीफ सीजन में अच्छे उत्पादन और रबी सीजन में भारी पैदावार की संभावना की अहम भूमिका
- चालू कीमतों पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि 2019-20 में 11.30 फीसदी रहने का अनुमान
- किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलने के आसार क्योंकि महंगाई 10.2 फीसदी रहने का अनुमान
- एनएसओ का अनुमान है कि पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि स्थिर कीमतों पर 3.7 फीसदी रहेगी

सड़क, सिटी गैस और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सुधार देख रहा स्टेट बैंक

नम्रता आचार्य और ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 28 फरवरी

कॉर्पोरेट को दिए जाने वाले कर्ज में कुल मिलाकर सुस्ती है, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने आज कहा कि सड़क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में बेहतरी नजर आ रही है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) पर आयोजित एक सेमीनार में हिस्सा लेने आए स्टेट बैंक के कमर्शियल क्लाइंड ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर पीएन प्रसाद ने कहा, 'हम कुछ क्षेत्रों की परियोजनाओं के वित्तपोषण में ताजा निवेश देख रहे हैं। इनमें सड़क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और अक्षय ऊर्जा शामिल है। स्टेट बैंक अक्षय ऊर्जा के बड़े प्रस्तावों और परियोजनाओं के मूल्यांकन में लगा है। ऐसे में हम इन क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत देख रहे हैं।'

इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से पिछली तिमाही में कर्ज की मांग बढ़ी है, जिससे कुल मिलाकर कर्ज की मांग को बल मिला है।

प्रसाद ने कहा, 'हमने पाया है कि पिछली तिमाही में कर्ज लेने की मात्रा बढ़ी है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओर से मांग बढ़ने के कारण कर्ज की मांग गति पकड़ेगी। कर्ज लेने की मात्रा में 5 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।'

स्टेट बैंक की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब कर्ज की वृद्धि में रिकॉर्ड कमी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक क्रेडिट चालू वित्त वर्ष के दौरान 6.5 से 7 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, जो पिछले 58 साल में सबसे सुस्त बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर कॉर्पोरेट उधारी में वृद्धि इस साल 0.5 या 1 प्रतिशत रह सकती है, जो सामान्यतया 7 से 8 प्रतिशत होती है। प्रसाद ने कहा कि तमाम कंपनियां अपनी कार्यशील पूंजी क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं और कुछ इसे वापस कर रही हैं।

प्रसाद ने कहा, 'हमने इसकी दो वजहें पाई हैं। कंपनियां नई परियोजनाओं में निवेश नहीं कर रही हैं और वे बेकार में पैसे रखे को इच्छुक नहीं हैं, इसलिए वे कार्यशील पूंजी कर्ज का भुगतान कर रही हैं, जिससे कि उनकी लागत कम हो सके। मांग में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसलिए वे अपनी कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल कम कर रही हैं।'

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसएसओ) की ओर से जारी हाल के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2019 में 0.3 प्रतिशत गिरा है। ताप बिजली परियोजनाओं, एनबीएफसी और वाणिज्यिक रियल एस्टेट जैसे कुछ क्षेत्रों में दबाव है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी क्षेत्र में बैंक का बकाया 1.70 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें निवेश भी शामिल है।

हो रहा है बदलाव

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से पिछली तिमाही में कर्ज की मांग बढ़ी
- ताप बिजली परियोजनाओं, एनबीएफसी और वाणिज्यिक रियल एस्टेट जैसे कुछ क्षेत्रों में दबाव
- लागत घटाने के लिए तमाम कंपनियां अपनी कार्यशील पूंजी कर रही हैं वापस
- रसायन, रत्न एवं आभूषण और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ क्षेत्रों पर हो सकता है कोरोनावायरस का असर

कोरोनावायरस का असर

प्रसाद ने कहा कि अब तक बैंकिंग क्षेत्र पर कोरोनावायरस के कारण कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन आगे चलकर कुछ जोखिम हो सकता है। उन्होंने कहा, 'रसायन, रत्न एवं आभूषण और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ क्षेत्रों में कोरोनावायरस के कारण बैंक के कर्ज पर असर पड़ सकता है। बैंक स्थिति की निगरानी कर रहा है। सभी वैश्विक प्रगति पर नजदीकी से नजर रखी जाती है। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र इसे देख रहा है कि धन जुटाने और उधारी पर इसका कैसा असर रहेगा।'

राजकोषीय घाटा अनुमान के पार

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 28 फरवरी

केंद्र का राजकोषीय घाटा जनवरी अंत में पूरे साल के लिए तय अनुमान से 128.5 प्रतिशत बढ़कर 9,85 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। 2019-20 के संशोधित अनुमान में घाटा 7.7 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में घाटा संशोधित बजट अनुमान का 121.5 प्रतिशत रहा था। लेखा महानियंत्रक की ओर से आज जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पूंजीगत व्यय ज्यादा रहने और कर संग्रह व विनिवेश से प्राप्तियां कम रहने के कारण ऐसा हुआ है।

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और प्राप्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। वास्तविक रूप से यह घाटा 9,85,472 करोड़ रुपये रहा। सरकार ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 7,66,846 करोड़ रुपये रहने का बजट अनुमान रखा है। इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नैयर ने कहा, 'सामान्यतया हर वित्त वर्ष में केंद्र की प्राप्तियां उसके व्यय से ज्यादा होती हैं। इसकी वजह से पूरे साल का राजकोषीय घाटा लक्ष्य पर बना रहता है। हमारा अनुमान है कि केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियां पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम रहेंगी।' इस महीने संसद में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के अनुमान को 3.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.8 प्रतिशत कर दिया। इसका कारण राजस्व संग्रह में कमी बताया गया है। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के मासिक लेखा आंकड़े के अनुसार राजस्व प्राप्ति अप्रैल-जनवरी में 12.5 लाख करोड़ रुपये रही। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान का 67.6 प्रतिशत है। एक साल पहले इसी अवधि में यह संशोधित अनुमान का 68.3 प्रतिशत रहा था।

मुसलमानों को पांच फीसदी कोटा देने का प्रस्ताव

महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। कांग्रेस विधायक शरद रणपिसे के सवाल के जवाब में मंत्री ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में जल्द ही एक कानून पारित हो। उन्होंने सदन में कहा कि स्कूलों में प्रवेश शुरू होने से पहले इस बारे में 'उचित कदम' उठाए जाएंगे। *बीएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 12

छिटपुट सुधार से परे

शायद सरकार का यह कहना सही है कि अर्थव्यवस्था उस निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है जहां से केवल सुधार की संभावना है। शुक्रवार को जारी आर्थिक वृद्धि के तिमाही आंकड़े इसका समर्थन करते हैं और निवेश बैंकों के अर्थशास्त्री भी मोटे तौर पर इसकी पुष्टि करते हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी यह भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आने वाले वर्ष में भारत में मामूली सुधार देखने को मिलेगा। इस बात पर सहमति है कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है और मंदी भी अपना चरम देख चुकी है। इससे सरकार के प्रवक्ताओं को प्रोत्साहन मिला है और वे यह कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था एक चक्रीय प्रकृति की मंदी से गुजरी और वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं ने संकट में इजाफा किया। उनका यह भी कहना है कि यह सिलसिला भी सुधार पर है।

हमें ऐसे अनुमानों को लेकर सतर्क रहना होगा जो प्रमुख तौर पर घरेलू कारकों के आंशिक विश्लेषण पर आधारित है। मसलन शेष विश्व के साथ भारत की आर्थिक संबद्धता चाहे जितनी कमजोर हो, लेकिन उसका आर्थिक प्रदर्शन वैश्विक रुझानों के साथ सुसंगत ही है, हालांकि वह एकदम उसके अनुरूप नहीं है। यानी नई सदी के पहले दशक में भारत की तेज वृद्धि वाले वर्ष अप्रत्याशित वैश्विक वृद्धि को ही प्रतिबिंबित कर रहे थे जो विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 4.2 फीसदी थी। उसकी तुलना में वर्ष 2019 तक के पांच वर्ष में वैश्विक वृद्धि एक तिहाई गिरकर 2.8 फीसदी रह गई। भारत की वृद्धि भी हाल के वर्षों में तेजी से गिरी है।

अन्य ब्रिक्स देशों की कहानी भी काफी हद तक ऐसी ही है, हालांकि वहां ठीक इन्हीं वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। रूस की वृद्धि उच्च वृद्धि वाले वर्षों के 7 फीसदी से गिरकर हाल के समय में 1 फीसदी की आधी रह गई। ब्राजील में भारी उतार-चढ़ाव आए और 2013 तक के चार वर्ष में उसने 4 फीसदी वृद्धि हासिल की जबकि उसके बाद वहां वृद्धि ऋणात्मक हो गई। हाल के तीन वर्षों में वह बमुश्किल 1 फीसदी की वृद्धि हासिल कर पाया। चीन में भी धीमापन आया है और वह अपने सर्वश्रेष्ठ समय की तुलना में आधी वृद्धि ही हासिल कर पाया है। अब कोरोनावायरस के कारण इसमें और गिरावट आएगी। अन्य उभरते बाजारों की हालत भी ऐसी ही है। तुर्की में वृद्धि बेहतरीन वर्षों के 8 फीसदी से घटकर 5.5 फीसदी हो गई और अब यह 3 फीसदी से कम वृद्धि दर्ज कर रहा है। हमें अंतरराष्ट्रीय रुझानों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर उभरते बाजारों के रुझानों पर।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

यहां चार बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली बात है कोरोनावायरस के सर्वव्यापी महामारी बनने के खतरे की। दुनिया भर के बाजार इसे लेकर चिंतित हैं। दूसरी बात है वैश्विक व्यापार वृद्धि में मंदी। विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक वाणिज्यिक व्यापार को आर्थिक वृद्धि की दर के समकक्ष रखा है जबकि करीब दो दशक तक व्यापार वृद्धि की दर विश्व अर्थव्यवस्था से 40 फीसदी तक अधिक रही है। यह बदलाव आंशिक रूप से तो इसलिए है क्योंकि विभिन्न देशों के बीच विवाद उत्पन्न हुए और उसके परिणामस्वरूप संरक्षणवाद लागू किया गया। परंतु इसकी अन्य वजह भी हैं। व्यापार जगत में शीघ्र सुधार की उम्मीद नहीं है।

तीसरा कारक वह है जिसे विश्व बैंक उभरते बाजारों की उत्पादकता वृद्धि में कमी के रूप में दर्ज करता है। देश में यह एकदम स्पष्ट रूप से हमारे सामने है क्योंकि आर्थिक वृद्धि निवेश दर की तुलना में तेजी से गिरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत को अब समान वृद्धि दर हासिल करने के लिए पहले की तुलना में अधिक निवेश की आवश्यकता है। आखिर में वे जोखिम आते हैं जो वैश्विक कर्ज से संबंधित हैं। इससे मुद्रा बाजारों में असामान्यता आ रही है क्योंकि निवेश दर ऋणात्मक है। एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जिन्हें झटके लगने की ज्यादा आशंका है।

इन तमाम बातों के पहले देश में बचत और निवेश दर बढ़ाने की चुनौती है। इसके अलावा मानव संसाधन को बेहतर बनाने, खेतों में उत्पादकता बढ़ाने, राजकोषीय दबाव से निपटने की जुगत करने, सही नीतियों के साथ रोजगार तैयार करने और बाजार में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की चुनौती शामिल है। चक्रीय कारकों के काम करने के बावजूद सुधार की गति और गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इन कार्यों को कितनी तवज्जो दी जाती है। इसके बिना वृद्धि कमजोर बनी रहने की आशंका है। यह 6.6 फीसदी के मौजूदा दीर्घावधि के औसत से भी कम रह सकती है। मौजूदा वैश्विक संदर्भ में यह चाहे जितना असंतोषजनक हो लेकिन हमें इसका भी अहसानमंद रहना होगा।

बिनय सिन्हा

ट्रंप की यात्रा से संबंधों को मिली नई नींव

भारत-अमेरिका संबंधों को नई दिशा देने में ट्रंप की यात्रा एक हद तक सफल मानी जा सकती है। हालांकि अब भी कई मसले हैं जिन पर दोनों देशों को काफी काम करना है। बता रहे हैं **श्याम सरन**

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की हालिया भारत यात्रा में अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ है और दोनों देशों के संबंधों को नए मुकाम तक पहुंचाने की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति का घरेलू स्तर पर चुनावी व्यस्तताओं के बावजूद भारत की यात्रा पर आना भारत के साथ संबंधों से जुड़ी अहमियत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को एक भव्य मंच मुहैया कराया जो अमेरिका में उनके मतदाताओं को लुभाने में कारगर साबित होगा। ट्रंप के पास अपनी विदेश नीति के मोर्चे पर दिखाने को थोड़ी सफलताएं ही हैं लेकिन यह दौरा एक चमकदार बिंदु माना जाएगा। अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी तेजी से समृद्ध एवं रसूखदार हो रहे हैं और वे 'भारत के दोस्त' का समर्थन करने का मन बना सकते हैं। हम ब्रिटेन में हाल में संपन्न चुनावों की पुनरावृत्ति अमेरिका में भी देख सकते हैं जहां 'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' ने टोरी नेताओं के पक्ष में खुलकर लामबंदी की जबकि लेबर पार्टी पर हमलावर रहा। अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के दावेदार बर्नी सैंडर्स के कश्मीर मुद्दे पर लगातार दिए जा रहे बयानों को देखते हुए ऐसे अभियानों से इनकार नहीं किया जा सकता है जिनमें भारतीय-अमेरिकी नागरिकों को डेमोक्रेट उम्मीदवार को वोट देने से रोका जा सके। ट्रंप के खेमे को यह अच्छा लगेगा लेकिन इससे पिछले दो दशकों से अमेरिका के दोनों दलों से भारत को मिल रहा समर्थन प्रभावित होगा।

दरअसल ट्रंप ने मोदी को उनकी दी हुई सौगात लौटाई है। यह एक ऐसा शिखर सम्मेलन था जहां ट्रंप ने सारी अच्छी बातें कीं, मोदी एवं उनके नेतृत्व की जमकर तारीफ की और कश्मीर या नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों पर अपने मेजबान को असहज स्थिति में डालने वाली किसी भी टिप्पणी से पूरी तरह परहेज किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक सफल बहुलवादी एवं विविधतापूर्ण देश के रूप में भारत और एक उदार लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता की तारीफ कर मोदी के घरेलू एवं विदेशी आलोचकों को सार्वजनिक रूप से झिड़की लगाई। सार्वजनिक प्रशंसा पर फलने-फूलने वाले और विशाल पैमाने पर राजनीतिक प्रदर्शन में माहिर नेताओं के तौर पर ट्रंप एवं मोदी दोनों को इस यात्रा से बहुत कुछ मिला है। हालांकि यात्रा के दौरान ही राजधानी की सड़कों पर हुई हिंसा की घटनाओं ने मोदी के लिए इस चमक को थोड़ा फीका कर दिया लेकिन दौरे की सुखद अनुभूति आगे भी बनी रहेगी। क्या इस दौरे का कोई सार नहीं था? वास्तव में ऐसा था। ट्रंप ने व्यापार के मुद्दे पर भारतीय रुख को लेकर खासा संयम दिखाया। अमेरिका से किए जाने आयात पर भारत द्वारा लगाए गए शुल्क को लेकर उनकी शिकायत एक हद तक संयत थी। उनका नजरिया आशावादी एवं आगे की तरफ देखने वाला था, भले ही एक विशाल एवं महत्त्वाकांक्षी व्यापार समझौता हो पाने फिलहाल अवास्तविक लग रहा है। दोनों ही पक्षों पर एक सीमित समझौता करने का भारी दबाव था लेकिन मतभेदों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इस संबंध के आर्थिक स्तंभ आगे भी डांवाडोल बने रहेंगे लेकिन फिलहाल राहत मिली है।

राजनीतिक एवं सुरक्षा के मुद्दों पर ठोस नतीजे सामने आए हैं। औपचारिक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत-अमेरिका रिश्ते को 'समग्र वैश्विक सामरिक भागीदारी' के स्तर पर ले जाने की घोषणा की गई है। इस शब्दावली का मतलब है कि दोनों देशों के बीच कहीं अधिक व्यापक एवं करीबी सुरक्षा संबंध होंगे। हिंद-प्रशांत की संकल्पना का प्रमुखता से जिक्र हुआ है लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि यह फॉर्मूला अमेरिका की पसंद वाली अधिक सीमित भौगोलिक अवधारणा को दर्शाता है, मसलन हॉलीवुड टु बॉलीवुड या पश्चिमी प्रशांत। हिंद-प्रशांत के प्रमुख अवयव के तौर पर आसियान केंद्रीयता का उल्लेख यह भी दिखाता है कि परिचालन के स्तर पर भारत अधिक सीमित परिभाषा स्वीकार करता है, भले ही आलंकारिक रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र हिंद महासागर के पश्चिमी पाटों तक जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर भारतीय एवं अमेरिकी सैन्यबलों की अंतर-सक्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि समय के साथ इसका विस्तार दूसरे साझेदार देशों तक भी हो सकता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के लिए 'चतुर्पक्षीय' शब्दावली का पहली बार औपचारिक इस्तेमाल भी इस साझा बयान का एक अहम तत्त्व रहा। यह इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है कि भारत अब चीन या रूस की उतनी चिंता नहीं करता है जो इस सैन्य गठबंधन को 'एशियाई नाटो' बताते रहे हैं। इसके पहले भारत चतुर्पक्षीय शब्द का इस्तेमाल किए जाने के पक्ष में था और उसकी जगह 'बहुपक्षीय' शब्द चाहता था।

चीन और आसियान के बीच दक्षिण चीन सागर में एक कानूनी आचार संहिता को लेकर जारी बातचीत का भी इस बयान में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह सभी देशों के वैध अधिकारों एवं हितों को अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं है। चीन ने जोर दिया है कि यह संहिता क्षेत्र से बाहर के देशों को सुरक्षा एवं आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से अलग रखती है जब तक कि संबंधित पक्षों के बीच सहमति न हो जाए। साफ है कि कोरोनावायरस के प्रकोप से जूझ रहा चीन जवाबी प्रहार की अधिक गुंजाइश देता है।

अफगानिस्तान के बारे में जो नहीं कहा गया है वह बयान में उल्लिखित बिंदु से कहीं अधिक अहम है। इस बयान में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में बैठक के दौरान शांति समझौता होने की संभावना और अफगानिस्तान में युद्धविराम का कोई जिक्र नहीं है। यह भारत के लिए चिंता की बात है और कोई भी देख सकता है कि बयान में नए घटनाक्रम क्यों नहीं नजर आ रहे? अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताओं का ध्यान नहीं रखे जाने के एवज में सीमापार आतंकवाद का विस्तार से उल्लेख और पाकिस्तान में स्थित विभिन्न आतंकवादी संगठनों की सूची जारी करने के कदम हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की राह बनाने में पाकिस्तान की भूमिका काफी अहम है।

भारत-अमेरिका परमाणु सौदे के तहत छह अमेरिकी नाभिकीय रिएक्टरों की खरीद पर प्रगति की भी संभावना है। इसके अलावा अमेरिकी तेल एवं गैस की बिक्री में हुई वृद्धि को अमेरिका के लिए और बड़ा बाजार मुहैया कराने में नाकामी के हर्जाने के तौर पर देखा जा रहा है। लेनदेन की यह सोच एक बार तो काम कर सकती है लेकिन कृषि उत्पादों के लिए बाजार मुहैया कराने एवं बौद्धिक संपदा संरक्षण जैसे पुराने मसलों पर अमेरिकी व्यापार प्रतिष्ठान के रुख में नरमी आने की संभावना कम ही है।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अस्थिर, तुनकमिजाज और अप्रत्याशित स्वभाव वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को सलीके से संभालने में बेहतरीन सियासी कौशल का प्रदर्शन किया और उन्हें अपने स्वभाव के विपरीत संयम बरतने और सोच-समझकर टिप्पणियां करने की स्थिति में ले आए। केवल सीएनएन के एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते समय ही ट्रंप थोड़ा भटके थे। अगर ट्रंप नवंबर में होने वाले चुनाव में जीतते हैं तो मोदी के साथ उनके निजी संबंध काफी काम आएंगे। शायद भारत भी इसी पर दांव लगा रहा है।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो हैं)

रुपहले पर्दे की उजली चमक में छिपे उम्मीद भरे सबक

यह अच्छी खबरों का एक टुकड़ा भर है लेकिन इस पर टिके रहने लायक है। भारतीयों ने वर्ष 2019 में फिल्मों के कुल 1.03 अरब टिकट खरीदे। ऑर्मेक्स मीडिया बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक यह आंकड़ा वर्ष 2018 की तुलना में नौ फीसदी अधिक है जब 94.5 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई थी। यह वृद्धि बहुत अधिक न होते हुए भी तीन कारणों से अच्छी खबर है।

पहला, यह भारत के 1.67 लाख करोड़ रुपये के मीडिया एवं मनोरंजन बाजार के लिए खराब रहे साल का इकलौता उजला पहलू है। आर्थिक सुस्ती, टेलीविजन प्रसारण के लिए चैनलों की कीमत तय करने का ट्राई का फैसला और इस उद्योग की वृद्धि एवं रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी व्यापक नीति का पूर्ण अभाव होने से वर्ष 2019 इस क्षेत्र के लिए निराशाजनक रहा। विज्ञापन राजस्वों में वृद्धि एक अंक में गिर चुकी है जबकि भुगतान राजस्व के मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ रहा है। किसी भी बड़े सूचीबद्ध मीडिया समूह- ज़ी एंटरटेनमेंट, नेटवर्क18, जागरण प्रकाशन या डीबी कॉर्पोरेशन की तिमाही रिपोर्टों को देखें तो खबर अच्छी नहीं है। डिज्नी स्टार और टाइम्स ग्रुप जैसी हरेक बड़ी गैरसूचीबद्ध फर्म को लक्ष्य हासिल करने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अभी तक के साक्ष्य महज आख्यान हैं लेकिन नौकरियां तो गई हैं। ध्यान रखें कि टीवी एवं प्रिंट माध्यम मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के अगुआ हैं। टेलीविजन अकेले आधा राजस्व जुटाता है जबकि प्रिंट इस उद्योग का 18 फीसदी से अधिक राजस्व जुटाता है। जहां तक फिल्म उद्योग का सवाल है तो वह महज 10 फीसदी राजस्व ही ला पाता है।

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का यह मतलब है कि फिल्मों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों से भी बढ़िया सौदा मिलता है।

और इसी बिंदु से हम दूसरे कारण तक पहुंचते हैं। करीब चार वर्षों से टिकटों की संख्या गिर रही थी या स्थिर बनी हुई थी जबकि औसत टिकट मूल्य लगातार बढ़ रहा था। बेचे जाने वाले टिकटों की संख्या आम तौर पर 80 करोड़ से लेकर 90 करोड़ के बीच में थी। लेकिन मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष में भारत की शीर्ष तीन मल्टीप्लेक्स शृंखलाओं में तीन वर्षों के बाद टिकट बिक्री में उछाल देखने को मिली। ऑर्मेक्स की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर उछाल की पुष्टि करती है और दिखाती है कि 2019 में पूरे साल यह मजबूत बनी रही। मोटे रुझानों के हिसाब से देखें तो रिपोर्ट अधिक भाषाओं, बेहतर कहानियों और पहले सप्ताहांत पर निर्भरता कम करने पर जोर देती है जिससे यह वृद्धि आगे भी जारी रहे।

इनमें से सबसे अहम वह तरीका है जिससे भारत की विविधता आंकड़ों में नजर आ रही है। एक अरब से अधिक टिकटों की बिक्री और 10,948 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस राजस्व संग्रह हिंदी, तमिल, तेलुगू, हॉलीवुड और अन्य फिल्मों के बीच बंटा हुआ था। ऑर्मेक्स मीडिया के मुख्य कार्याधिकारी शैलेश कपूर कहते हैं, 'कुल मिलाकर भाषा काफी अहम होती जा रही है। हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म साहो का 60 फीसदी से अधिक बॉक्स ऑफिस राजस्व हिंदी संस्करण से आया। इसी तरह हिंदी फिल्म वॉर का कुछ कारोबार तेलुगू संस्करण से भी आया। हम एक ऐसे परिदृश्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें शीर्ष दस में शामिल कई फिल्में बहु-भाषाई हैं।'

हॉलीवुड फिल्मों का ही उदाहरण लेते हैं। इनकी राजस्व हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2018 में कुल बॉक्स ऑफिस संग्रह में हॉलीवुड फिल्मों का योगदान 12.5 फीसदी रहा था जो 2019 में बढ़कर 15 फीसदी हो गया। लेकिन इसकी वजह यह है कि हॉलीवुड फिल्मों को अब एक साथ हिंदी, तमिल, तेलुगू और कुछ अन्य भाषाओं में भी डब कर रिलीज किया जा रहा है। इस बारे में कपूर कहते हैं, 'अवेंजर्स फिल्म का 40-45 फीसदी राजस्व हिंदी, तमिल एवं तेलुगू संस्करणों से आया। यह बात सभी फ्रैंचाइजी या बड़ी फिल्मों के लिए सही है जिनका औसतन 35 फीसदी राजस्व भारतीय भाषाओं से आता है।'

दूसरी भारतीय भाषाओं में डब या रीमेक हुई हिंदी फिल्मों के बारे में भी यही स्थिति है। यही हाल हिंदी में डब या रीमेक होने वाली गैर-हिंदी फिल्मों का है। बहुभाषाई फिल्में के टिकट अधिक बिक रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस राजस्व में शीर्ष पर हैं।

इस रिपोर्ट के अच्छी खबर होने का तीसरा कारण यह है कि अब अधिक लोग फिल्में देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख करने लगे हैं। फिल्म उद्योग के राजस्व का 70 फीसदी से अधिक राजस्व टिकट बिक्री से आने की वजह से यह काफी अहमियत रखता है। निश्चित रूप से फिल्मों की पहुंच एवं प्रभाव एक अरब टिकटों की बिक्री से बहुत आगे तक जाता है। कुल टीवी दर्शकों में से एक चौथाई लोग अपने घरों में फिल्में देखते हैं। भारत में स्ट्रीमिंग वीडियो ब्रांड फिल्मों एवं फिल्म-संबंधी सामग्रियों पर असंगत रूप से अधिक वक्त देते हैं। लेकिन फिल्म उद्योग तो बुनियादी तौर पर बॉक्स ऑफिस से अपना पैसा कमाता है। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का यह मतलब है कि फिल्मों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों से भी बढ़िया सौदा मिलता है।

लेकिन हमें याद रखना होगा कि यह अच्छी खबर का एक फलक भर है। इसके जरिये समूचे परिदृश्य को खुशनुमा दिखाने की कोशिश बरगलाने वाली मानी जाएगी। जैसा कि एक मंत्री ने हाल ही में किया था। कई लोग यह दलील दे सकते हैं कि अधिक लोगों के फिल्म देखने सिनेमाघर जाने का मतलब यह है कि देश में कोई आर्थिक सुस्ती नहीं है। यह एक दोषपूर्ण तर्क है। इसका कारण यह है कि अगर टिकट बिक्री ही देश की वृहद-आर्थिक सेहत का पैमाना है तो फिर हम इसके पहले के चार वर्षों में भारी मंदी के दौर से गुजर रहे थे।

कानाफूसी

मध्य प्रदेश संदेश: शर्मिंदगी का सबब

मध्य प्रदेश शासन की पत्रिका मध्य प्रदेश संदेश का जनवरी अंक प्रदेश सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया। दरअसल हुआ यह कि पत्रिका में प्रकाशित महात्मा जिंदा हैं शीर्षक वाले एक लेख में स्वतंत्र लेखिका श्वेता रानी ने लिखा कि कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं जबकि कुछ अन्य लोग शहीद मानते हैं। इस पत्रिका के प्रकाशित होने के बाद ही छात्रों, शिक्षक समुदाय और कुछ राजनेताओं के भारी विरोध के चलते सरकार फौरन हरकत में आई और उसने पत्रिका के संपादक मनोज खरे को संपादक के पद से हटा दिया। मनोज खरे राज्य के जनसंपर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

कसीनो से बचाव

उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा को पिछले दिनों विधानसभा में उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब प्रयागराज उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुझाव दिया कि कर राजस्व में इजाफा करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कसीनो को कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाए। वाजपेयी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग जुआ खेलने नेपाल जाते हैं जिससे प्रदेश को पूंजी का नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि वह इसकी इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि राज्य के भोले-भाले लोगों और उसकी संस्कृति की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। बहरहाल वाजपेयी के सुझावों से सत्ता पक्ष में घबराहट फैल गई। बाद में उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना वाजपेयी से बातचीत करते देखे गए।

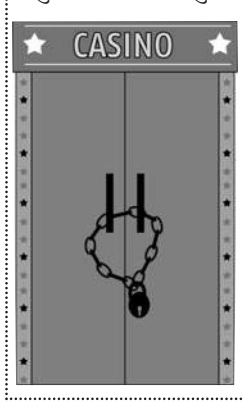

आपका पक्ष

आरटीआई के प्रति लोगों में जागरूकता

देश को आजाद हुए एक लंबा समय बीत चुका है। देश ने भले ही विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की की हो, लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं और सरकारों के इसपर नकेल कसने के दावे भी खोखले हो चुके हैं और आम जनता का विश्वास सरकार पर से उठ चुका है। घोटालों की खबरों और सरकारी विभागों में आम जनता को भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों में परेशानियों का सामना करने से भ्रष्टाचार का घिनौना चेहरा दिख ही जाता है। हर सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकारें कुछ ही गंभीर दिखती हैं। लेकिन हाल में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के पीठ ने न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को भी सूचना के

हाल में उच्चतम न्यायालय का कार्यालय सूचना का अधिकार कानून के अधीन लाया गया

अधिकार कानून के अधीन लाने का रास्ता साफ कर दिया। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से देश को कितना फायदा पहुंचेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आरटीआई की धारा में कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिसके तहत कुछ मामलों में सूचना नहीं देने का आधार भी है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि यह अधिनियम सूचना देने में सत प्रतिशत सक्षम है। मोदी सरकार को इन धाराओं में भी संशोधन करना चाहिए। कई लोग सूचना के अधिकार से भी अनजान हैं। उन्हें इसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकार भी गंभीरता नहीं दिखाती है। अगर देश के सभी नागरिक इस अधिनियम के प्रति जागरूक हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि वह लोगों को इसके प्रति जागरूक करे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

केजरीवाल की रणनीतिक जीत

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का बहुत ही नकारात्मक प्रचार अभियान उसके खिलाफ ही गया और भाजपा अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई। केजरीवाल ने चुनाव से दो साल पहले मोहल्ला क्लीनिक, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए तमाम सौगातें आदि देने का जो काम किया था, उसका भरपूर प्रचार शुरू कर दिया। भाजपा अपने ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता, शाहीनबाग के नाम पर जनता के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रही और जब उसे केजरीवाल की रणनीति समझ में आई तो उसने कुछ स्कूलों का स्टिंग आदि कर आप के दावों की पोल खोलने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर, केजरीवाल ने दिल्ली के विकास पुरुष का चोला पहन खुद को दिल्ली का बेटा बताकर लोगों के सामने पेश कर दिया। नतीजा सबके सामने है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कोरोनावायरस से जिंस बाजार लुढ़का

जस्ता, एल्युमीनियम साल के निचले स्तर पर, तेल, चांदी में भारी गिरावट

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 28 फरवरी

कोरोनावायरस के दुनियाभर में प्रभाव की वजह से वैश्विक स्तर पर इक्विटी में हुई बिकवाली का असर जिंस बाजारों पर भी दिखा है। प्रमुख वैश्विक जिंसों की कीमतें शुक्रवार को 1-1.32 प्रतिशत तक लुढ़क गईं। भारत में यह गिरावट लगभग 1 प्रतिशत रही और शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 72.17 पर बंद हुआ।

लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर सभी प्रमुख धातुओं में 1.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। लंदन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस समेत ऊर्जा खंड में 1.2 प्रतिशत तक की कमी आई।

जापान और चीन में ब्याज दरों में गिरावट का रुझान दिखने से वैश्विक आर्थिक प्रोत्साहन की भी शुरुआत हुई है जिससे बेस मेटल और ऊर्जा की मांग कमजोर हो सकती है।

कोटक सिक्योरिटीज की सहायक उपाध्यक्ष प्रियंका जवेरी ने कहा, 'चीन से बाहर सामने आ रहे कोरोनावायरस के नए मामलों की खबरों के बाद वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है और इससे शुक्रवार को जिंस कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि चीन ने इस महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज किए हैं, लेकिन अन्य देशों में इसके प्रसार से कारोबारी तबके में चिंता बढ़ गई है। जब तक कोरोनावायरस पर काबू नहीं पाया जाता, जब तक वैश्विक जिंसों में सुधार मुश्किल दिख रहा है।'

दुनियाभर में कोरोनावायरस के मामले बढ़ने के बाद शुक्रवार को वैश्विक जिंस कीमतों में कच्चे तेल पर आधारित तेज गिरावट दर्ज की गई। इससे उन देशों में व्यापारी ज्यादा प्रभावित हुआ है जहां कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी है।

भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मई निपटान अनुबंध के लिए कच्चा तेल वायदा 3.06 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ शुक्रवार दोपहर को 3,291 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि इसका पूर्ववर्ती बंद स्तर 3,395 रुपये प्रति बैरल था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, कच्चा तेल 1.2 प्रतिशत तक गिरकर 50.20 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। डब्ल्यूटीआई ऑयल 45 डॉलर के आसपास है।

एलएमई पर प्रमुख धातुएं साल के निचले स्तर पर आ गईं। तीन महीने आगे की एल्युमीनियम कीमतें 0.8 प्रतिशत गिरकर 1,676 डॉलर प्रति टन रह गई हैं जो 40 महीने यानी 2016 से सबसे कम हैं। इसी तरह तीन महीने की जस्ता कीमतें 2.1 प्रतिशत तक गिरकर 1,970 डॉलर प्रति टन पर रह गई हैं जो जून 2016 के बाद से सबसे निचला स्तर है। शुक्रवार को तीन महीने की निकल कीमतें 1.5 प्रतिशत घटकर 12,185 डॉलर और तांबा 1.1 प्रतिशत गिरकर 5,552 डॉलर प्रति टन पर कारोबार कर रहा था। लंदन में शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में सीसा 0.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,795 डॉलर प्रति टन पर था।

आनंद राठी शेयर्स ऐंड स्टॉकब्रोकर्स लिमिटेड के निदेशक (जिंस एवं मुद्रा) नवीन माथुर ने कहा, 'प्रमुख धातुओं में गिरावट का अन्य दौर देखा गया है क्योंकि कोरोनावायरस से जुड़ा प्रभाव इक्विटी से लेकर सराफा, ऊर्जा से लेकर औद्योगिक धातुओं, सभी पर देखा जा रहा है। एमसीएक्स पर जस्ता गिरा है, क्योंकि कोरोनावायरस के प्रभाव ने लगभग हरेक उत्पाद की बिक्री प्रभावित की है, जिनमें कारों और वाशिंग मशीन से लेकर जिपर्स और हाईवे क्रैश-बैरियर्स आदि तक शामिल हैं।'

इस बीच, कई देशों द्वारा कोरोनावायरस को देखते हुए यात्रा संबंधी चेतावनियां जारी किए जाने से वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा झटका लगा है। वुहान समेत चीन के कई बाजारों में दुकानें और कारखाने बंद पड़े हैं। इस वजह से विश्लेषक जनवरी और मार्च 2020 के बीच की तिमाही में इसका ज्यादा प्रभाव महसूस किए जाने की आशंका जता रहे हैं।

लंदन मेटल एक्सचेंज में जिंसों के दाम

एलएमई 3 माह फॉरवर्ड	28 फरवरी	अंतर % (1 दिन)
तांबा डॉलर/टन	5,552	-1.1
एल्युमीनियम डॉलर/टन	1,676	-0.8
सीसा डॉलर/टन	1,759	-0.8
निकल डॉलर/टन	12,185	-1.5
जस्ता डॉलर/टन	1,970.5	-2.1
क्रूड तेल डॉलर/बैरल	50.2	-1.2
सोना रुपये/10 ग्राम	42,354	-0.2
चांदी रुपये/किलो	45,515	-3.2

स्रोत- लंदन मेटल एक्सचेंज, इंडिया बुलियन ऐंड ज्वैलर्स एसोसिएशन

एल्युमीनियम-जिंक उत्पादों पर डंपिंगरोधी शुल्क

वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाने के लिए चीन, वियतनाम और दक्षिण कोरिया से आने वाले एल्युमीनियम तथा जस्ते के कुछ उत्पादों पर डंपिंगरोधी शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। मंत्रालय की अन्वेषण इकाई डीजीटीआर ने 14.3 डॉलर से 173.1 डॉलर प्रति टन के दायरे में शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। यह सुझाव एल्युमीनियम और जिंक के लेप वाले उत्पादों पर शुल्क लगाने के लिए है।

डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा, 'इन देशों से संबंधित उत्पादों के आयात पर डंपिंगरोधी शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है।' डीजीटीआर ने डंपिंग के आरोपों की जांच करने के बाद पाया कि इन उत्पादों को सामान्य मूल्य से कम दरों पर भारत लाया गया। इससे घरेलू उद्यमों को नुकसान हुआ है।

जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स ने इन उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाने का आवेदन डीजीटीआर को दिया था। डीजीटीआर ने कंपनी द्वारा पर्याप्त सबूत दिए जाने के आधार पर पिछले साल अप्रैल में जांच शुरू की थी। *भाषा*

बीएस बातचीत

एमसीएक्स की रीब्रांडिंग पर रहेगा जोर : पी एस रेड्डी

कमोडिटीज एक्सचेंज में जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने साक्षात्कार में एमसीएक्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी **पी एस रेड्डी** ने **राजेश भयानी** को कई नई पहल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आलू और बिजली वायदा जैसे उत्पादों में दिलचस्पी और डेरिवेटिव प्लेटफॉर्मों पर गोल्ड ईटीएफ पर जोर दिए जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

कमोडिटी क्षेत्र में एमसीएक्स के लिए किस तरह की संभावना देख रहे हैं?

हम देख रहे हैं कि यह एक्सचेंज सभी जिंसों के लिए एक प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है। हमने एमसीएक्स के लिए रीब्रांडिंग पहल पर भी ध्यान दिया है जिसे एमसीएक्स के लिए नए लोगो के साथ वित्त वर्ष 2021 में पूरा कर लिया जाएगा। हम कृषि जिंसों के कारोबार के लिए अच्छी संभावना देख रहे हैं। हमने एमसीएक्स की स्थिति मौजूदा धातु तथा ऊर्जा एक्सचेंज के साथ साथ कमोडिटीज एक्सचेंज के तौर पर मजबूत बनाए जाने पर जोर दिया है।

सरकार ने हाल में सोने के लिए इंडिया गोल्ड डिलिवरी स्टैंडर्ड्स जारी किया है। इसका एक्सचेंज पर गोल्ड डेरिवेटिव पर क्या असर पड़ेगा?

एक उद्योग-व्यापी समूह (एसीएक्स शामिल) ने बीआईएस को इंडिया गुड डिलिवरी स्टैंडर्ड का मसौदा सौंपा था, जिसके बारे में जनवरी 2020 में आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। इसमें सराफा के लिए उत्पाद और तकनीकी मानक शामिल किए गए हैं। मौजूदा समय में सिर्फ लंदन बुलियन मेटल एसोसिएशन (एलबीएमए) प्रमाणित रिफाइनरियों द्वारा परिष्कृत सोने को ही एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। हालांकि, हम भारतीय सराफा रिफाइनरियों (भले ही वे एलबीएमए से मान्यताप्राप्त न हों) से गोल्ड डेरिवेटिव की अनुमति के लिए जांच प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुके हैं। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इस तरह की जांच प्रक्रिया में रिफाइनिंग और क्षमताओं की परख के साथ साथ जिम्मेदार खरीदारी एवं आपूर्ति श्रृंखला के लिए ओईसीडी दिशा-निर्देशों के पालन के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के मानकों वाली बेंचमार्किंग प्रक्रिया शामिल है। हम गुणवत्ता मानकों के साथ सख्त अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्पाद डिलिवरी सूची का विस्तार कर इसमें घरेलू रिफाइनरियों को शामिल किया है। हम उन ऑडिटरों के संपर्क में हैं, जो जवाबदेह खरीदारी और आपूर्ति श्रृंखला के लिए ओईसीडी दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।

अनिवार्य डिलिवरी पर अमल के बाद बेस मेटल डेरिवेटिव में गिरावट देखी गई है। आपने खोए हुए कारोबार को पुनः पटरी पर लाने के लिए क्या योजना बनाई है?

सभी धातु अनुबंधों में डिलिवरी-आधारित निपटान अनिवार्य बनाए जाने के बाद कारोबार में कमी आई है। नियामक की सलाह को ध्यान में रखते हुए हमने सभी धातुओं के लिए डिलिवरी आकार में बदलाव किया है। हालांकि हेजर और बड़ी कंपनियां हेजिंग बढ़ाने के लिए विभिन्न डिलिवरी आकार चाहते हैं। इसलिए, हम जस्ता, सीसा और एल्युमीनियम अनुबंधों के आकार बदल रहे हैं। इन आकार को जून अनुबंधों से 5 टन से 1 टन किया जा रहा है। इससे इन धातुओं में वास्तविक हेजिंग के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमने धातु उत्पादकों, उपभोक्ताओं और रिफाइनरों के साथ उनके हेजिंग व्यवसाय बढ़ाने की संभावना को लेकर चर्चा की है। हमारा जोर इस सेगमेंट में खोया आधार लौटाने पर रहेगा।

एक्सचेंज किन नए उत्पादों को पेश करने की योजना बना रहा है?

हमारे पास शुरू में आलू वायदा था और हम इसे पुनः पेश किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमने आगरा वेरायटी के आलू वायदा की ट्रेडिंग की अनुमति देने की योजना बनाई है। हमारी योजना में अन्य उत्पाद बिजली वायदा है और हम इसके लिए यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस संबंध में बाजार नियामक के तौर पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) काम करेगा या केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

काफी समय पहले म्युचुअल फंडों को अनुमति दी गई थी। क्या आप इन्हें पेश करने की योजना बना रहे हैं?

हम म्युचुअल फंडों (एमएफ) को लेकर आशान्वित हैं। हमने एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के साथ संपर्क किया है और उससे अनुरोध किया है कि वह गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) को डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होने को कहे। प्रस्ताव के तहत ईटीएफ अपनी जरूरत के अनुसार एमसीएक्स वायदा पर सोना खरीद सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इसे रोलओवर कर सकते हैं। मौजूदा समय में वे पारंपरिक तौर पर सोने की खरीदारी करते हैं।

छह और देशों में फैला कोरोनावायरस

संक्रमण के डर से यात्रा प्रतिबंध और आपूर्ति में बाधा से अमेरिका और यूरो क्षेत्र में मंदी के दिख रहे हैं आसार

रॉयटर्स

कोरोनावायरस के महामारी बनने का खतरा पैदा हो गया है। छह और देशों में पहली बार इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चेतावनी दी है कि यह दुनियाभर में फैल सकता है। इस बीमारी के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए स्विटजरलैंड ने जिनेवा कार शो रद्द कर दिया है।

मंदी के संकेत

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से शेयर की कीमतों के लिहाज से यह सबसे खराब सप्ताह रहा। इसकी वजह वायरस संक्रमण के डर से अंतरराष्ट्रीय यात्रा और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं रहीं जिससे अमेरिका और यूरो क्षेत्र में मंदी की आशंका और गहरा गई। वॉल स्ट्रीट पर एशियाई शेयरों में भारी गिरावट देखी गई जहां बेंचमार्क एसऐंडपी 500 सूचकांक गुरुवार को 4 फीसदी से अधिक लुढ़क गया। इस तरह 19 फरवरी के इसके उच्च स्तर पर बंद होने के मुकाबले 10 फीसदी से अधिक की कमी आ चुकी है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैल सकती है और अमेरिका में वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक सुस्ती के आसार हैं।

मित्सुबिशी यूएफजे मॉर्गन स्टैनली सिक्योरिटीज में मुख्य निवेश रणनीतिकार नोरीहीरो फुजितो ने कहा, 'कोरोनावायरस अब वैश्विक महामारी का रूप लेता नजर आ रहा है हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं बाजार बड़े जोखिम का सामना कर पाने में सक्षम हैं।' चीन में संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 78,800 हो गई है जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या करीब 2,800 हो चुकी है। चार और देशों में कोरोनावायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है और इसके साथ ही चीन से बाहर इससे संक्रमित होने वाले देशों और क्षेत्रों की संख्या 55 हो चुकी है जिनमें संक्रमण के 4,200 से अधिक मामले की पुष्टि हुई है और करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है। अब संक्रमण के नए मामलों में से करीब तीन-चौथाई मामले चीन को छोड़कर बाकी देशों में नजर आ रहे हैं।

इटली का एक व्यक्ति इस हफ्ते नाइजीरिया पहुंचा जिसमें कोरोनावायरस की पुष्टि हुई है। अफ्रीका की सर्वाधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया में यह पहला मामला सामने आया है। इसी तरह ईरान से उड़ान भरकर न्यूजीलैंड वापस जाने वाले व्यक्ति में इस वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और यह यहां का पहला मामला है। पूर्वी यूरोप, बेलारूस और लिथुआनिया में भी पहले मामले की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रॉस एडहानोम गेब्रेयस ने कहा कि सभी देशों को संक्रमण से बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। टेड्रॉस ने गुरुवार को जिनेवा में कहा, 'इस वायरस में वैश्विक महामारी का रूप धारण करने की संभावना है। यह डरने का समय नहीं है बल्कि संक्रमण को रोकने और जीवन बचाने के लिए कदम उठाने का वक्त है।'

- चीन में संक्रमण के नए मामले में कमी के रुझान दिख रहे हैं
- ईरान, इटली और दक्षिण कोरिया संक्रमण से जूझ रहे हैं
- बाजार में लगातार छठे सत्र में भी बरकरार रही गिरावट
- अमेरिका में वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक सुस्ती के पूरे संकेत
- संक्रमण के तीन-चौथाई मामले चीन से बाहर दिख रहे हैं
- दक्षिण कोरिया में कोरोनावायरस संक्रमण ज्यादा गहराया है

निर्णायक कदम

मंगोलिया में अभी तक संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन उसने सावधानी बरतते हुए चीन से यात्रा कर वापस लौटे अपने राष्ट्रपति बतुल्गा खाल्तमा को चिकित्सा निगरानी में रखा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस वायरस को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं है और इसका टीका तैयार करने में 18 महीने तक का वक्त लग सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का प्रशासन सुरक्षा उपकरण का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है।

यूरोप की बात करें तो फ्रांस में संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की संख्या दोगुनी हो चुकी है वहीं जर्मनी ने भी महामारी की आशंका जताई है और ग्रीस जो पश्चिम एशिया से जाने वाले शरणार्थियों के जाने का रास्ता है, उसने कठोर सीमा नियंत्रणों की घोषणा की है। यूरोप में इटली सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है जहां संक्रमण से मरने वालों की संख्या 17 पर पहुंच गई और वायरस की पुष्टि वाले मामलों की संख्या 200 से अधिक बढ़कर 655 हो गई। जर्मनी में संक्रमण के करीब 45 मामले, फ्रांस में करीब 38 और स्पेन में 23 की पुष्टि हो चुकी है।

ओलिंपिक पर संदेह

चीन से बाहर दक्षिण कोरिया में ही कोरोनावायरस संक्रमण के सर्वाधिक मामलों की पुष्टि हुई है जबकि शुक्रवार को संक्रमण के 571 नए मामले सामने आए जिससे कुल संक्रमित लोगों की तादाद 2,337 हो गई। संक्रमण से दक्षिण कोरिया में 13 लोगों की जान गई है। डब्ल्यूएचओ के आपात कार्यक्रम के प्रमुख डॉ माइक रेयान ने कहा कि ईरान में इसका प्रसार आशंका से ज्यादा हुआ है। चीन से बाहर सबसे अधिक मौतें यहीं हुई है। यहां 245 रिपोर्ट किए गए मामलों में से 26 लोगों की जान गई है। सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ईरान के साथ-साथ भारत में भी कोरोनावायरस के प्रसार पर नजर बनाए हुए हैं।

2020 ओलिंपिक का आयोजन इस साल जुलाई में जापान में होना निर्धारित है लेकिन रेयान ने कहा कि आयोजनकर्ताओं के साथ इस पर चर्चा चल रही है कि इस आयोजन पर आगे बढ़ा जाए या नहीं। अगले हफ्ते ओलिंपिक आयोजनकर्ता परंपरागत मशाल दौड़ के दौरान फैसला लेंगे। यह 20 मार्च को यहां 121 दिनों की यात्रा के लिए पहुंचेगा जिसके मार्ग में फुजी पर्वत और हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क जैसे स्थल भी शामिल हैं। शुक्रवार को जापान में संक्रमण के नए मामलों की संख्या 200 से अधिक हो गई और चार लोगों की मौत हो गई।

हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट चाहती हैं सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पांच सदस्यीय शिष्टमंडल का गठन किया जो दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके उन्हें रिपोर्ट सौंपेगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार सोनिया ने मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर और सुष्मिता देव को जिम्मेदारी दी है कि वे उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि ये शिष्टमंडल प्रभावित इलाकों का दौरा करने के तत्काल बाद सोनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर लोगों को उकसा कर दंगे करवा रहे हैं और वे भ्रम फैला रहे हैं कि नए कानून के कारण मुस्लिम अपनी नागरिकता गवां देंगे।

कांग्रेस ने भाजपा द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधने के बाद शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान राजधर्म में समानता और सद्भाव पर जोर दिया गया, जबकि भाजपा के शासन में विभाजनकारी मानसिकता हावी है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पलटवार किया कि अगर राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) का विरोध करना राष्ट्रविरोधी बात है तो भाजपा सरकार को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। दिल्ली हिंसा पर सरकार को राजधर्म का पालन करने की सोनिया गांधी की नसीहत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास वोट बैंक की राजनीति के लिए अधिकारों का दमन करने, अपनी बात से पलटने का रहा है इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राजधर्म पर उपदेश न दें।

कांग्रेस शिष्टमंडल इन इलाकों का दौरा कर देगा रिपोर्ट

विपक्षी दलों की पहल

कई गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कहा है कि वह दिल्ली में शांति बहाली और भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देश दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माकपा, भाकपा, राजद, द्रमुक और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी के हालात पर चर्चा के लिए कोविंद से मिलने का समय मांगा है। पत्र में विपक्षी नेताओं ने कहा, 'दिल्ली के उप राज्यपाल एवं प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया जाए कि जल्द शांति बहाल हो और भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए।' सीएए को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 42 लोगों की मौत हुई और 250 से अधिक लोग घायल हो गए। *एजेंसी*

निजी स्तर पर सामाजिक क्षेत्र में बढ़ा योगदान

सुरजीत दास गुप्ता

परोपकार से जुड़े कामों और देश के सामाजिक क्षेत्र के लिए निजी स्तर पर जुटाया गया धन वर्ष 2017-18 में 70,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर रहा जिसमें पिछले 8 सालों के दौरान सालाना 14-18 फीसदी चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है। सरकार ने विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर लगाम लगाने की कोशिश की है जिसकी वजह से विदेशी फंडों के योगदान में नाटकीय रूप से कमी आई है। सामाजिक परोपकारिता के लिए वित्त वर्ष 2018 में निजी तौर पर लोगों ने योगदान दिया जिसमें उनका योगदान करीब 43,000 करोड़ रुपये है। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में घरेलू कंपनियों के योगदान में कमी देखी जा रही है। बेन ऐंड कंपनी द्वारा रिलीज की गई 'इंडिया फिलैंथ्रॉपी रिपोर्ट 2020' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 में विदेशी स्रोत का फंडिंग में केवल 21 फीसदी का योगदान रहा जो वित्त वर्ष 2010 के 50 फीसदी से कम हो गया। वित्त वर्ष 2015 में इनकी हिस्सेदारी 33 फीसदी थी। विदेशी फंडिंग में कमी की वजह यह है कि सरकार ने विदेशी योगदान नियमन कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन करने के लिए एनजीओ के खिलाफ व्यापक पैमाने पर लगाम लगाने का अभियान शुरू कर दिया।

सामाजिक क्षेत्र के लिए इन फंडों में निजी स्तर पर हिस्सेदारी बढ़ी जो वित्त वर्ष 2010 में महज 26 फीसदी थी जो वित्त वर्ष 2018 में 61 फीसदी से अधिक हो गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय मूल के 11 परिवारों ने योगदान दिया जिनमें किरण मजूमदार शॉ, डॉ रोमेश, कैथलीन वाधवानी, अजीम और यास्मीन प्रेमजी और नंदन तथा रोहिनी नीलेकणि शामिल हैं जिनके योगदान से प्राइवेट फंडिंग में काफी तेजी देखी गई। ये परिवार 'गिविंग प्लेज' से जुड़े हैं जिसके जरिये वैश्विक स्तर के अरबपति परोपकार से जुड़े कार्यों के लिए अपनी संपत्ति का अहम हिस्सा दान करते हैं। हैरानी की बात है कि भौगोलिक स्तर पर परोपकारिता फंडिंग गरीबी के पैमाने या असुरक्षा के दूसरे निर्देशकों से जुड़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर राज्यवार आधार पर परोपकार निवेश में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 34 फीसदी है हालांकि गरीबी की दर 17.35 फीसदी है। वहीं इसके उलट झारखंड को परोपकार से जुड़े कार्यों के निवेश का एक फीसदी से भी कम मिलता है जबकि गरीबी की दर 36.96 फीसदी तक है। फंड के इस्तेमाल और ज्यादा जरूरत वाले निवेश क्षेत्र के बीच कोई संबंध नहीं है। मिसाल के तौर पर घरेलू कॉरपोरेट समाजिक दायित्व फंडिंग में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी तक है। कुल फंड में स्त्री-पुरुष समानता के लिए एक फीसदी खर्च किया जाता है। इन संसाधनों का एक-तिहाई हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब 12 करोड़ किशोर लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए तत्काल 11,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।

बायोकॉन की चेयरमैन व प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ, विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ऐसी प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों की निजी फंडिंग की तेजी में योगदान दिया है

ऑनलाइन मार्केटिंग पर बॉलीवुड का बढ़ता जोर

सोहिनी दास

पिछले कुछ हफ्ते में शायद ही किसी के डिजिटल मेल बॉक्स में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने वाला संदेश न मिला हो। दरअसल यह संदेश फिल्म 'थप्पड़' की अभिनेत्री तापसी पन्नू दे रही हैं जिनकी यह फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो गई है। महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा फिल्म 'थप्पड़' की मुख्य थीम है। आप इसे फिल्म के प्रचार-प्रसार की मार्केटिंग रणनीति भी कह सकते हैं। तापसी कहती हैं, 'आप मेरे साथ खड़े हो जाइए और दुनिया को बताइए कि एक थप्पड़, बस इतनी सी बात नहीं है।'

बॉलीवुड में फिल्म की मार्केटिंग करने वाले फिल्म के प्रचार-प्रसार में जितना खर्च करते हैं उसके मुकाबले ऑनलाइन माध्यम के जरिये बेहद कम रकम खर्च की गई है। डिजिटल माध्यम से पेश किए जा रहे इस तरह के संदेश को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी दिखी और इसी वजह से फिल्म को लेकर चर्चा चल रही है। इसी तरह पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' भी ऑनलाइन मंचों पर समलैंगिक अधिकारों से जुड़ी चर्चा का हिस्सा रही जिसने अब तक 32.6 करोड़ रुपये तक कमाए हैं। फिल्म स्टूडियो अपने डिजिटल दायरे का विस्तार करते हुए फिल्म से जुड़े खास पोस्टर, मीम और ट्रेलर रिलीज करते हैं ताकि दर्शकों को प्रभावित किया जा सके। दरअसल ये अपने मार्केटिंग बजट का किफायती तरीके से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं ताकि ऑनलाइन चैनलों में इनका दायरा और दबदबा बढ़े।

एक मार्केटिंग अधिकारी कहती हैं कि फिल्म निर्माता अब डिजिटल मार्केटिंग को खर्च के बोझ के तौर पर नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि यह एक निवेश है जो कम से कम 2 करोड़ रुपये और अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक हो सकता है। उनके मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग में पैसे का इस्तेमाल प्रभावी रूप से किया जा सकता है और खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का इस्तेमाल किया जा सकता है।

डिजिटल एवं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी दि स्मॉल बिग आइडिया के सीईओ और सह संस्थापक हरिकृष्णनन पिल्लई कहते हैं, 'कुछ साल पहले तक फिल्म मार्केटिंग सितारों तक सीमित रहती थी। एक बड़े अभिनेता के दम पर दर्शकों को जुटाने की कोशिश होती थी लेकिन अब इसमें बदलाव आ चुका है।' वह फिल्म 'बधाई हो' की मिसाल देते हैं जिसकी कहानी बिल्कुल अलग तरह की थी और वह फिल्म हिट रही। इसे महज 29 करोड़ के बजट से बनाया गया था लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 140 करोड़ रुपये कमा लिए। इस फिल्म में कोई बड़ा सितारा नहीं था लेकिन मार्केटिंग टीम ने फिल्म की कहानी पर जोर देते हुए फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसी झलक और संवाद को शामिल किया जिससे दर्शकों में इस फिल्म को देखने की उत्सुकता बढ़ी। डेटा का इस्तेमाल संदेश के प्रभाव और पहुंच को तय करने के लिए किया जाता है।

तापसी पन्नू ने 'थप्पड़' फिल्म के लिए ऑनलाइन प्रचार किया